नवम्बर - 2024 वर्ष -9 अंक - 11

मीडिया मैप

उदार जनतंत्र का सजग प्रहरी

शुल्क -50

हम क्यों...

मीडिया मैप एक वैचारिक पत्रिका है। मीडिया जगत के नीतिपरक और मूल्यनिष्ठ बिन्दु तथा इनसे जुड़ाव रखने वाले आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक मुद्दे इसकी विषयवस्तु है। मीडिया मैप की संपादकीय नीति उदारवादी, आधुनिक, प्रगतिशील व सर्वधर्म समभाव की भावना पर आधारित है। मीडिया मैप हमारे बहुलतावादी समाज की विविधताओं से सृजित समस्त सोच, विचार, दृष्टिकोण, मूल्य और मान्यताओं को अपने में समाहित करने का एक प्रयास है । हमारा उद्देश्य वैज्ञानिक सोच द्वारा समाज से जुड़े मूल मुद्दों पर एक प्रबुद्ध जनमत विकसित करना है जिससे देश में संकुचित मानसिकता और आपसी टकराव से उपर उठकर एक उच्चस्तरीय विचार-विमर्श का वातावरण तैयार हो सके।

मीडिया मैप

संपादकीय सलाहकार मंडल
डॉ. रामजीलाल जांगिड
डॉ बलदेवराज गुप्त
डॉ जॉन दयाल
डॉ गौहर रजा
मंगल सिंह आजाद

संपादक
प्रदीप माथुर

संयुक्त संपादक
सतीश मिश्रा

सहयोगी संपादक
अमिताभ श्रीवास्तव

ब्यूरो प्रमुख
राजीव माथुर

मुख्य सह-संपादक
प्रशांत गौतम

सह-संपादक
अंकुर कुमार

मुख्य प्रबंधक
जगदीश गौतम

विधि परामर्शदाता
संजय माथुर

पंजीकृत कार्यलय
2325, सेक्टर - डी , पॉकेट - 2 ,
वसंतकुंज , नई दिल्ली

कार्यालय
69 ज्ञानखंड-4 इंदिरापुरम
गाजियाबाद-201014

दूरभाष - 9810385757 / 9910069262

एम बी के एम फाउंडेशन प्रकाशन

ईमेल-
editor@mediamap.co.in

संपादकीय
पत्र पाठको के
एक झलक पिछले अंक की
विचार प्रवाह
नवम्बर 14 : पंडित जवाहर लाल नेहरू जयंती
नेहरू विरोधी अभियान का वास्तविक कारण और उसका आर्थिक पहलू — प्रो प्रदीप माथुर — 8
आर्थिक सुधार और विकास के लिए आज गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता — प्रशांत गौतम — 10
नवम्बर 11 : शिक्षा दिवस
ऑनलाइन शिक्षा के तरीके में सुधार की आवश्यकता — डॉ. अनुभव माथुर — 13
क्या ऑनलाइन पढ़ाई मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है? — अमिताभ श्रीवास्तव — 14
नवंबर 14 : बाल दिवस
'प्रयास' के जुगनुओं की उड़ान — अमिताभ श्रीवास्तव — 15
विविधा
तेज रफ्तार ले रही है हजारों लोगों की जान — डॉ मुजफ्फर हुसैन ग़ज़ाली — 18
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पर स्मारक व्याख्यान — मीडिया मैप न्यूज़ — 20
जैव विविधता को हानि: भारत सबसे खराब पांच देशों में शामिल — डॉ. सतीश मिश्रा — 23
आर्थिक जगत
भारत की आर्थिक समृद्धि के दावे कितने सही, कितने खोखले — प्रो शिवाजी सरकार — 25
देश-विदेश
ब्रिक्स सम्मेलन : भारत-चीन मित्रता का सन्देश सबसे बड़ी उपलब्धि — गोपाल मिश्रा — 27
राज्यों से
राजनीति समीकरणो को बदलते पंजाब के उपचुनाव — प्रभजोत सिंह — 29
उमर अब्दुल्ला के लिए मुख्यमंत्री पद काँटों का एक ताज — अश्विनी कुमार — 31
श्रीमती इंदिरा गाँधी जन्मदिवस: 19 नवंबर
इंदिरा गाँधी, निहित स्वार्थों का षड्यंत्र और आपातकाल — प्रो प्रदीप माथुर — 33
राजनीति परिदृश्य
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सौ वर्ष: एक आलोचनात्मक मूल्यांकन — डॉ. सतीश मिश्रा — 36
महिला जगत
महिलाओं पर हिंसा : सुरक्षा और सम्मान की आवश्यकता — इंदु रानी सिंह — 38
कथा साहित्य
कड़वी-मीठी गोली — दिनेश नारायण वर्मा — 40
हास्य व्यंग
गधा आदरणीय, है क्योकि गधेपन की है भरमार — अनूप श्रीवास्तव — 42

पत्र पाठको के

अरुण माथुर - बधाई हो जी, सभी लेख अद्भुत एवं आनंददायक हैं।

डॉ उमा त्रिपाठी - नई पत्रिका का जन्म उत्साहवर्धक है। आपका एडिटोरियल एडवाइजर होना इसे ऊर्जा देगा। "गाँधी के दुष्प्रचार की हक़ीक़त " अच्छा लेख है। -----अशेष शुभकामनाएं। ----- सादर चरण स्पर्श।

डॉ जॉन दयाल - उत्कृष्ट पत्रिका

एक झलक पिछले अंक की

हमारे देश में गांधी की छवि पर होते छद्म हमले!

निहित स्वार्थी और कट्टरपंथी तत्व गांधी के समय भी उनके उदार और समावेशी विचारों और उनकी लोकप्रियता से परेशान होकर जब तब उन पर तरह तरह के आरोप लगाते रहते थे जिनमें कई संस्थाओं, यथा मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा एवं आर एस एस से जुडे कुछ लोग, वामपंथी और डॉ अम्बेडकर आदि प्रमुख थे। ऐसा करने वाले काफी लोग अंग्रेज सरकार से विविध लाभ के पद आदि भी लेते थे। उन दिनों भी गांधी के चरित्र और व्यक्तित्व पर फूहड़ता की हद छूते उस तरह के लांछन नहीं लगते थे जिस तरह की कीचड इधर पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर एक नियोजित षडयंत्र की तरह फैलाई जा रही है। यह विडंबना देखिए कि जैसे जैसे गांधी की छवि वैश्विक पटल पर दिन ब दिन मजबूत होकर और ज्यादा निखरती जा रही है जिसकी एक झलक संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रुप में मनाने की घोषणा कर और अपने परिसर में उनकी मूर्ति स्थापित कर विश्व को दिखाई है, ऐसे समय में हमारे अपने देश में उस महामानव को बौना साबित करने के कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं। - **डॉ आर के पालीवाल**

शास्त्री जी मेरे पिता, मेरे गुरु और मेरे आदर्श

शास्त्री जी, मेरे बाबूजी, उनकी ईमानदारी, सरलता और सादगी आज भी लोगों के दिलों में बसी है। यही कारण है कि आज भी उनके प्रति लोगों का अटूट प्यार है। उन्हें देखकर लोगों को यह महसूस होता था कि वह किसी बड़े नेता से नहीं, बल्कि अपने ही बीच के एक साधारण व्यक्ति से मिल रहे हैं। शास्त्री जी की यही विनम्रता उन्हें जनता के दिलों में खास स्थान दिलाती थी। लोगों को लगता था कि वह हमारे ही बीच के एक आदमी हैं, जो आज देश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। - **सुनील शास्त्री**

इंदिरा गांधी जैसा मैंने उन्हें जाना, समझा

स्वतंत्र भारत की तीसरी प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी की पारी और पत्रकारिता में मेरा प्रवेश लगभग एक साथ ही वर्ष 1966 में शुरू हुआ। उस समय से लेकर 1984 के अंत में उनकी हत्या तक ऐसा कोई दिन नहीं था जब पत्रकारों को श्रीमती इंदिरा गांधी से संबंधित कुछ न कुछ सोचना, बात करना, लिखना या संपादित करना न पड़ता हो। यह उन पत्रकारों के लिए अधिक आवश्यक होता था जिनकी रुचि समसमयकी मामलों और राजनीतिक विमर्श में थी। मेरी रुचि दोनों विषयों में ही थी।बजट: क्या विकास का लाभ आम आदमी तक पहुंचेगा?: - **प्रो प्रदीप माथुर**

कृपया इस बुजुर्ग आदमी पर दया करें

हम सभी 100 साल तक जीना चाहते हैं। लेकिन लंबी उम्र अक्सर बोझ बन जाती है, जैसा कि नारायण दत्त तिवारी के मामले में हुआ। चार बार मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल और देश के प्रधानमंत्री बनने से बाल-बाल बचे यह वरिष्ठ नेता 90 साल की उम्र में उपेक्षा और उपहास का जीवन जी रहे हैं। कई क्षेत्रों में उनके महान योगदान के लिए उन्हें एक वरिष्ठ राजनेता के रूप में सम्मानित किया जाना चाहिए। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय किया। और यह केवल उनका ही दुर्भाग्य नहीं है। यह हमारे समय की राजनीति पर एक दुखद टिप्पणी है। - **गोपाल मिश्रा**

आर्थिक विकास और सामाजिक विघटन का अंतर्द्वंद्व

दीपावली का पर्व बीते वर्ष के अच्छे बुरे काम और हानि लाभ का लेखा-जोखा करके नए वर्ष को नए आत्मविश्वास, आशा और प्रेरणा से शुरू करने का प्रतीक है। किसी राष्ट्र और समाज के जीवन के लिए भी समय समय पर अपनी दशा और दिशा का आकलन करना आवश्यक होता है। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमने बीते वर्ष में आर्थिक दृष्टि से अच्छी प्रगति की है। कोविड के दुष्प्रभाव को अतीत का घटनाक्रम बनाकर हमारी विकास दर 7% के उस स्तर पर पहुंची है जहाँ आज शायद विश्व का कोई भी बड़ा देश नहीं है। साथ ही साथ हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। हमारे देश के उद्योगधंधों में पूंजी का विदेशी पूंजी का नियोजन भी बढ़ा है और निर्यात में भी सकारात्मक रुझान है । पर साथ ही साथ देश में रोजगार के अवसर नहीं बढ़े और आज बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है । बेरोजगारी और मूल्यवृद्धि ने देश की बहुत बड़ी जनसंख्या को आज चिंता और निराशा के गर्त में धकेल दिया है।

आर्थिक विकास कुछ भी हुआ हो, सच तो यह है कि मोदी युग में समाज में आर्थिक असमानताएं बहुत बड़ी है।देश के संसाधन समाज के एक छोटे से वर्ग के हाथ में सीमित होकर रह गए हैं तथा सकल उत्पाद बढने का कोई भी लाभ आम आदमी को नहीं मिल रहा है। ये शर्म की बात है कि सरकार को देश की लगभग आधी आबादी को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है।

चाहे अर्थव्यवस्था में सुधार, उदारीकरण और आर्थिक विकास के कितने भी सशक्त तर्क दिए जाएं, बढ़ती हुई आर्थिक असमानताओं को किसी भी तरह नज़रन्दाज़ नहीं किया जा सकता। गिरती मांग, घटी उत्पादकता और बेरोजगारी का अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव तो बढ़ती हुई आर्थिक असमानताओं का एक स्वाभाविक परिणाम है। पर हमारे लिए इसके समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का भी मूल्यांकन करना आवश्यक है।

बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई से भारतीय समाज में जो निराश भाव आया है उसकी अभिव्यक्ति, आपसी टकराव, वैमनस्य, आक्रोश तथा असभ्य वार पलटवार और असहशीलता में देखी जा सकती है। इसने हमारी राजनीतिक सभ्यता, मूल्यो और सौहार्दपूर्ण सामाजिक व्यवहार को दूषित किया है।

पर इससे भी अधिक भयानक बात है कि यह आर्थिक असन्तुलन गलत मूल्यों को प्रोत्साहन देकर सामाजिक विघटन का कारण बन रहा है। ईमानदारी, सच्चाई, सेवा, त्याग, आपसी सहयोग और छोटे, कमजोर और असहाय लोगों के लिए सहानुभूति या कुछ करने की भावना जैसे उन सामाजिक मूल्यों का अंत हो रहा है जिन्होंने हर तरह की परिस्थितियों में हमारे समाज की रक्षा की और उसकी मानवतावादी संस्कृति को अक्षुण रखा है।

महिलाओं पर अत्याचार, यहाँ तक कि अबोध बालिकाओं का बलात्कार, बुजुर्ग और असहाय माता पिता को घर से निकालना, जरा सी बात पर सड़क पर लड़ना और हिंसा पर उतर आना और विरोधियो और विधर्मियों को आक्रामक प्रचार का निशाना बनाना इसी सामाजिक विघटन का परिणाम है। इसलिए आवश्यक है कि हम समय रहते अपने समाज में पनप रही इन हिंसक और आक्रामक प्रवृत्तियाँ को की गंभीरता को समझे और अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को ही अपनी प्रगति और सुशासन का संकेत समझने की भूल ना करें।

इस दीपावली के पर्व पर हमें अपने मन को भी इसी ज्ञान से प्रकाशित करने की आवश्यकता है।

प्रदीप माथुर

सिएटल में स्थापित गांधी प्रतिमा: विश्व में अहिंसा और शांति का संदेश

महात्मा गांधी की एक प्रतिमा 2 अक्टूबर को सिएटल सेंटर, सिएटल में प्रदर्शित की गई। यह प्रतिमा स्पेस नीडल के आधार के ठीक नीचे तथा चिहुली गार्डन एवं ग्लास म्यूजियम के समीप स्थापित की गई है।

वाशिंगटन राज्य के गवर्नर जे इंसली ने गांधी की शिक्षाओं के प्रति एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि के रूप में गांधी की प्रतिमा को मान्यता देते हुए एक आधिकारिक घोषणा जारी की है। उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा परिवर्तन लाने में अहिंसा के परिवर्तनकारी प्रभाव की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। इसके अतिरिक्त, किंग काउंटी द्वारा ग्रेटर सिएटल क्षेत्र के सभी 73 शहरों के लिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी दिवस के रूप में घोषित किया गया है।

अनावरण समारोह में सिएटल के मेयर ब्रूस हैरेल, कांग्रेसी एडम स्मिथ, कांग्रेसी जयपाल, प्रशांत नॉर्थवेस्ट में यूएस फर्स्ट कॉर्प्स की कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रमिला जेवियर ब्रूनसन, मार्टिन लूथर किंग-गांधी इनिशिएटिव के अध्यक्ष एडी राई और भारत के महावाणिज्यदूत प्रकाश गुप्ता शामिल थे। भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्य भी गांधी जयंती पर अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए उपस्थित थे।

गांधी जी के जन्मदिन को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जयंती समारोह में नेताओं ने अहिंसा (अहिंसा), सत्याग्रह (सत्य की शक्ति) और सर्वोदय (सभी के लिए कल्याण) के मूल्यों पर प्रकाश डाला जो आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं।

प्रतिमा के लिए स्थान का निर्णय भारत के महावाणिज्य दूतावास और सिएटल शहर के सहयोग से किया गया था, सिएटल सेंटर एक महत्वपूर्ण स्थान है; यह प्रतिवर्ष 12 मिलियन से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करता है और इस प्रकार महात्मा गांधी की प्रतिमा के लिए और शांति और अहिंसा के उनके मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए एक उपयुक्त और सुलभ स्थान है।

फिलिस्तीन में नरसंहार का महिमामंडन एक शर्मनाक बात

इजरायली जायनिस्ट व पश्चिमी साम्राज्यवादी प्रोपेगैंडा नीचता की सभी हदों को पार कर रहा है, नाजियों से भी कहीं बहुत अधिक नीचता। अब दो तीन दिन से पश्चिमी व जायनिस्ट दार्शनिकों -चिंतकों -बुद्धिजीवियों -पत्रकारों -मानवाधिकारियों वगैरह के कुछ ऐसे 'तर्क' वाले क्रमबद्ध लेख व बयान आने शुरू हुए हैं जिनका लब्बोलुआब है कि फलस्तीनियों का कत्लेआम करने में इजरायली फौजियों के साथ बड़ा भारी मानसिक उत्पीड़न हो रहा है जिसके लिए फलस्तीनियों को माफ नहीं किया जा सकता, चुनांचे उनका जनसंहार और तेज कर देना चाहिए।

मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा हूं कि कई नौजवान फौजियों के लिए खास तौर पर पश्चिमी देशों के आरामदायक जीवन से इजरायल लडने जाने वालों के लिए जिन्हें उम्मीद थी कि कुछ दिन फलस्तीनियों पर जुल्म का मजा लेकर लौट आएंगे, उनके लिए एक साल बाद भी इसका अंतहीन दिखना अब मुसीबत बन गया है। एकाध दो चार हत्या अलग बात है, साल भर लगातार बच्चों बूढ़ों औरतों समेत निहत्थे लोगों का निर्मम कत्ल, बच्चों के सिरों में गोली मारना, जिंदा लोगों को बुलडोजर से कुचल देना, पूरी इमारतों को निवासियों समेत जमींदोज कर देना, आसान काम नहीं है, उसके लिए करने वाले को खुद को इंसान मानने का दावा छोड़ना पड़ता है। पर इस तरह का पका हुआ मृतात्मा हत्यारा बनना भी सबके बस का नहीं है। 'मैकबेथ' में शेक्सपीयर व 'अपराध और दंड' में दोस्तोवस्की बहुत पहले इसके हस्र का वर्णन कर चुके हैं। वियतनाम में अमरीकी फौज इसका हस्र देख चुकी है - उन फौजियों का अधिकांश फिर कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाया, खुदकुशी, मानसिक बीमारी या आदतन अपराधी बनना, बहुतों के लिए यही विकल्प बचे। कोरिया में बमबारी से बस्तियों को नेस्तनाबूद करने वाले अमरीकी पाइलटों का भी ऐसा ही नतीजा था। फौज के बजाय कातिल लुटेरा गिरोह बन चुके इजरायली फौजियों का भी अब यही हो रहा है। कई के पहले ही खुदकुशी करने, मानसिक बीमार होने, लडने से मना करने, ड्यूटी छोडकर भागने की खबरें इजरायली मीडिया में आ रही हैं।

पर उन्होंने जो करना चुना उसका नतीजा यह तो होना ही था। इसके लिए अपने मौजूदा रूप में मरता हुआ इजरायली समाज व पूरी तरह सड़ती पश्चिमी बुर्जुआ सभ्यता जिम्मेदार है जिसने जनसंहार को आत्मग्लानि के बजाय आत्मगौरव का विषय बना दिया, जो इस तरह तो नाजी भी नहीं कर पाए थे। जितने वर्णन मिलते हैं वो भी अपने परिवार व समाज को यातना शिविरों में यहूदियों के कत्लेआम की विस्तृत जानकारी से अलग ही रख वहां सुसंस्कृत बने रहने की कोशिश करते रहे थे। जायनिस्टों व पश्चिमी बुर्जुआ समाज ने इस कत्लोगारत को सार्वजनिक-पारिवारिक आनंद व हास्य का विषय बना दिया। अब पश्चिमी मीडिया और बुद्धिजीवी इसके लिए खुद पश्चिमी साम्राज्यवाद व इजरायली जायनिस्टों को जिम्मेदार ठहराने के बजाय जिस तरह इसे भी फलस्तीनी जुर्म बता रहे हैं, वो तो नीचता का भी नीचतम स्तर ही कहा जाना चाहिए।

क्या कश्मीरी पंडित घाटी में वापस जायँगे

उमर अब्दुल्ला की जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में वापसी ने राज्य के राजनीतिक माहौल में नई ऊर्जा का संचार किया है। उनके पिता, फारूक अब्दुल्ला, ने कश्मीरी पंडितों से अपने घर लौटने की अपील की है, जो 1990 के दशक में आतंकवाद के कारण पलायन करने को मजबूर हुए थे। उन्होंने कहा कि अब राज्य में शांति स्थापित हो चुकी है और यह लौटने का सही समय है।

राज्य की राजनीतिक स्थिति में हाल के वर्षों में बदलाव आया है, विशेषकर 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद। उमर अब्दुल्ला की सरकार ने शांति और स्थिरता लाने की कोशिश की है, जिससे पर्यटन और निर्यात में सुधार हुआ है। हालाँकि, राज्य में अभी भी सुरक्षा चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जैसे पाकिस्तान से घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियाँ।

महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था में भी सुधार देखने को मिला है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद 2019 में 1.60 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023 में 2.46 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

फारूक अब्दुल्ला का कश्मीरी पंडितों की वापसी का आह्वान राज्य में स्थिरता और सांप्रदायिक सौहार्द की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। जम्मू-कश्मीर का भविष्य चुनौतियों से भरा है, लेकिन उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में राज्य एक स्थिर और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार है।

****

नवम्बर 14 : पंडित जवाहर लाल नेहरू जयंती

नेहरू विरोधी अभियान का असली कारण और उसका आर्थिक पहलू

प्रो प्रदीप माथुर

संघ परिवार की उच्च हिंदू वर्ग केन्द्रित राजनीति और जवाहरलाल नेहरू का पुरज़ोर विरोध भारतीय राजनीति का एक ऐसा विरोधाभास है जिसे समझना मुश्किल है। नेहरू जी उस कश्मीरी ब्राह्मण समाज से आते थे जो अपने को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण मानते हैं क्योंकि उनमें वैदिक काल की उस आर्य जाति का विशुद्ध रक्त है जिसने सनातन धर्म की नींव रखी थी।

सदैव नेहरू जी के नाम से पहले पंडित लगता था। मेरी पीढ़ी से पहले वाली पीढ़ी के लोग उनके संदर्भ में बात करते समय हमेशा उन्हें पंडितजी कहते थे ना कि नेहरू जी। ब्राह्मण होने के साथ साथ नेहरू जी उस कुलीनतंत्र से आते थे जिसकी रक्षा करने के लिए आरएसएस और भाजपा आज कटिबद्ध है और इस प्रयास में सब तरह की तिकड़मों और सच-झूठ का सहारा लेते हैं।

समाजवादी चिंतन और प्रगतिशील विचारोंवाले नेहरू जी कभी भी जातिवादी तो नहीं रहे, पर वह समाज सुधारक भी नहीं थे। उन्होंने कभी भी उस सामाजिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास नहीं किया जिसको संघ परिवार बनाए रखना चाहता है । यही नहीं भाजपा के सस्थापक और सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू जी के अनन्य प्रशंसक थे और नेहरू जी के देहावसान पर दिया गया उनका भाषण शायद नेहरू जी को दी गई सबसे भावभीनी श्रद्धांजलि है।

अत: यह समझ पाना मुश्किल लगता है कि नेहरू जी की मृत्यु के 70 वर्ष बाद भाजपा के सब छोटे बड़े नेता नेहरू जी की अनवरत आलोचना और उनके विरुद्ध घृणा अभियान में क्यों लगे हैं। वह भी जब आज नेहरू जी वर्तमान भारतीय राजनीति के लिए संदर्भहीन हो गए हैं?

मज़े की बात यह है कि नेहरू जी के विरुद्ध विष वमन करने वाले अधिकांश लोग वह हैं जिन्होंने नेहरू को न तो देखा, न सुना और न ही कभी पढ़ा है। और निश्चित रूप से वे हमारे स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान के बारे में कुछ भी नहीं जानते। फिर भी वे जवाहरलाल नेहरू को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और वे अपनी आलोचना में उतने ही उग्र हैं, जितने हमारे राजनीतिक इतिहास की समझ में वे अज्ञानी हैं।

सच है कि वर्तमान पीढ़ी का स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं के प्रति वैसा भावनात्मक लगाव नहीं है, जैसा पिछली पीढ़ी का था। लेकिन, आज के भारत की सभी कमियों के लिए नेहरू को ही क्यों जिम्मेदार ठहराया जाए। अगर कुछ गलत भी हुआ है, उसके लिए केवल उन्हें क्यों दोषी ठहराया जाए, जबकि सच्चाई यह है कि अगर आजादी के बाद देश की बागडोर नेहरू के हाथों में नहीं होती तो हालात आज और भी बदतर होते।

वर्ष 1962 में चीन द्वारा हमारी उत्तर-पूर्वी सीमाओं पर हमला करने और सीमा युद्ध में हमें अपमानित करने के बाद नेहरू ने अपनी अपील और सर्वप्रिय व्यक्ति जैसी छवि खो दी थी। डेढ़ साल बाद नेहरू की मृत्यु एक निराश व्यक्ति के रूप में हुई। लेकिन न तो उन 18 महीनों के दौरान और न ही उनके निधन के बाद उनके सबसे कड़े आलोचकों ने भी उन पर उस तरह से प्रहार नहीं किया जिस तरह से आज उन पर किया जा रहा है। अपने अधिकांश मित्रों और समकालीन लोगो के चले जाने के बाद नेहरू अब अपनी रक्षा करने में असहाय हैं और इन नेहरू आलोचकों को यह बतानेवाला कोई नहीं है कि आप लोग बिल्कुल गलत हैं।

जिस पीढ़ी ने चीन के विश्वासघात और अपमान का दर्द महसूस किया उसने नेहरू जी को कभी गाली नहीं दी। उन्होंने न तो उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया और न ही उनकी राजनीतिक बुद्धिमता पर। उनके आर्थिक विकास मॉडल की अक्सर यह कहकर आलोचना की जाती थी कि वह औद्योगीकरण के पक्ष में बहुत अधिक झुका हुआ है, लेकिन किसी ने भी भारत को आत्मनिर्भर देश बनाने की उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं उठाया। अगर देश की अर्थव्यवस्था आज मजबूत स्थिति में है, तो इसका मुख्य कारण इसका मजबूत बुनियादी ढांचा है, जिसकी नींव नेहरू ने उन लोगों के विरोध के बावजूद रखी थी जो अपनी नाक से आगे नहीं देख सकते थे।

अपने जीवनकाल के दौरान और श्रीमती इंदिरा गांधी के सत्ता में होने तक नेहरू के सबसे कटु आलोचक लोहिया के समाजवादी लोग थे। उन्हें लगता था कि

नेहरू इंडिया के हैं जबकि वे भारत से थे और उनके बीच एक बड़ी वर्गीय खाई थी जो उन्हें अलग करती थी। फिर भी वे नेहरू की आलोचना में कभी भी इस तरह नहीं गिरे और निश्चित रूप से वे आज के नेहरू विरोधियों की तरह नेहरू जी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे।

तो आज नेहरू के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों है? नेहरू के ये आलोचक वास्तव में कौन हैं और क्यों वे अपना गुस्सा निकालने के लिए नेहरू को ही चुनते हैं?

मेरे विचार में नेहरू की आलोचना करने वाले लोग किसी एक वर्ग से नहीं आते हैं। पर वे एक ही तरह के लोग हैं। उनकी सोच और प्रेरणा का स्रोत एक ही है।

वे युवा और मध्यम आयु के लोग हैं जो खुदरा व्यापार, बैंक, बीपीओ और वित्तीय विपणन में नौकरी करते हैं, वे प्रबंधन अधिकारी हैं जो छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायों को चलाते या प्रबंधित करते हैं और किसी भी तरह से पैसा बनाने के लिए गलाकाट प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। वे भवन निर्माण वृद्धि से लाभान्वित होने वाले लोग हैं जो समझते हैं कि देश की आवास समस्या का समाधान निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को आवासीय इकाइयां देना नहीं है बल्कि सपने बेचने से है। वे एयरलाइंस, होटल और आतिथ्य उद्योग से जुड़े लोग हैं।

मजे की बात यह है कि इनमें से कोई भी व्यक्ति नेहरू के बारे में कुछ भी नहीं जानता। भारत के इतिहास के बारे में उनका ज्ञान मुन्नाभाई स्तर का है। फिर भी उन्हें अपनी अज्ञानता पर न तो शर्म आती है और न ही उसे दूर करने की उन्हें कोई इच्छा है।

उनका साथ देने के लिए अन्य लोग भी हैं - शिक्षा जगत, मीडिया और मध्यम वर्ग में छद्म बुद्धिजीवी। चूंकि बदलते परिदृश्य को समझना कठिन है, इसलिए नेहरू पर हमला करना उनके लिए आसान है।

फिर संघ परिवार के अंदर और बाहर भी अधिकांश साम्प्रदायिक सोच वाले लोग हैं, जिन्हें भारत के सही इतिहास को समझने की सख्त जरूरत है।

लेकिन वे नेहरू के पीछे क्यों पड़े है?

इन सभी लोगो में एक बात समान है। वे आत्म-संयम, संस्थागत अनुशासन, कानून के शासन और पारदर्शिता से नफरत करते हैं। वे सफल होने के लिए अधीर हैं और "सब चलता है" के सिद्धांत की पूजा करते हैं।

नेहरू की आलोचना करने वाले भारतीय समाज की वर्ष 1990 के बाद की नई पीढ़ी से हैं जो वैश्वीकृत बाजार अर्थव्यवस्था के नए युग का उत्पाद है। पैसा ही उनका एकमात्र भगवान है और पैसा कमाने वाले व्यवसाय, उचित या अनुचित, उनके भगवान तक पहुँचने का रास्ता है। वे नैतिकता रहित बाजार संस्कृति के उत्पाद हैं। प्रबंधन शिक्षा ने उन्हें कौशल और दक्षता दी है, लेकिन कोई सामाजिक दृष्टिकोण नहीं दिया है। अल्पकालिक सफलता के लिए वे सभी व्यवहार संबंधी मानदंडों को तोड़ सकते हैं - व्यक्तिगत, सामाजिक और पेशेवर। हर्षद मेहता उनके आदर्श हो सकते हैं और गुरु उनकी पसंदीदा फिल्म हो सकती हैं। नाटककार विलियम शेक्सपीयर के चरित्र शाइलॉक के साथ कोई भी तुलना उन्हें बुरी नहीं लगती।

आजादी के बाद का भारत

क्या भारत की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के लिए नेहरू को ही दोष देना सही है? यह लेख आज के भारत में नेहरू की भूमिका पर विचार करता है।

लेकिन वे नेहरू को इतना नापसंद क्यों करते हैं?

वर्ष 1964 में जब नेहरू की मृत्यु हुई तब इनमें से अधिकांश लोगो का जन्म भी नहीं हुआ था। फिर भी वे जानते हैं कि नेहरू ने कहा था कि राज्य का व्यापार पर नियंत्रण होना चाहिए। - आर्थिक प्रगति और कॉर्पोरेट लूट एक ही चीज नहीं है - जब आप राजमार्ग, फ्लाईओवर, मल्टीप्लेक्स और मॉल जैसे बड़े निर्माण की योजना बनाते हैं तो आपको देश के गरीबों के बारे में भी सोचना चाहिए, जिन्हें अपने सिर पर छत की जरूरत है - संस्थागत कामकाज और प्रक्रियात्मक मानदंडों को तोड़कर आर्थिक प्रगति नहीं की जानी चाहिए और राज्य मशीनरी कदाचार को नियंत्रित करने के लिए है, न कि बेईमानी के व्यापार का समर्थन करने के लिए।

यह दर्शन ही नेहरू द्वारा भारत के छोटे लेकिन दृढ़ निश्चयी मध्यम वर्ग के लोगो को दी गई जबरदस्त नैतिक शक्ति है, जिससे यह सब कुछ चलता है वाला मतलब परस्त नया वर्ग नफरत करता है। इस वर्ग को आम आदमी का खून चूस कर अपना घर भरने से कोई ऐतराज नहीं है।

आधुनिक सोचवाले, सभ्य और कर्तव्यनिष्ठ भारतीयों के लिए नेहरू जी एक प्रतीक थे, जो चाहते हैं कि हमारे लोकाचार और हमारे स्वतंत्रता संग्राम द्वारा उत्पन्न आदर्शवाद को ध्यान में रखते हुए देश सही दिशा में विकसित हो। ऐसे लोग सार्वजनिक जीवन, नौकरशाही, न्यायपालिका, पुलिस, शिक्षा, मीडिया और सामाजिक कार्यों में रहे हैं। रिश्वत खिलाकर काम निकालने और उसे पर्यावरण प्रबंधन का नाम देनेवाले कॉर्पोरेट मालिकों के सब प्रयासों के बावजूद नेहरू के आदर्शवादी सोचवाले कई लोग अभी भी भ्रष्ट नहीं हैं। हालांकि वे काफी कमजोर हो गए हैं पर ऐसे लोग अभी भी इस देश की असंवेदनशील कॉर्पोरेट लूट का प्रतिरोध कर रहे हैं।

नेहरू पर हमला इस प्रतिरोध को कमजोर करता है और इन धन लोलुप शिकारियों के लिए दरवाजा खुला छोड़ देता है। उन्हें लूट की पूरी सुविधा मिले इसलिए नेहरू से नफरत करने वाले इस बड़े अभियान की आवश्यकता है वास्तव में नेहरू पर लगाएजाने वाले तमाम आरोप बिलकुल बेमानी है और इन लोगो के असली मकसद को छिपाने का एक प्रयास है।

****

लेखक : वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया गुरु एवं मीडिया मैप के संपादक हैं।

आर्थिक सुधार और विकास के लिए आज गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता

प्रशांत गौतम

हम गहरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं और इससे बाहर निकलने तथा देश को समावेशी आर्थिक विकास के मार्ग पर लाने के लिए सभी प्रकार के विकल्पों और विचारों पर विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि हम अतीत में वापस नहीं जा सकते हैं और अपने समय की समस्या को हल करने के लिए पुराने और अप्रचलित मॉडलों को लागू नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से अपने पूर्वजों के ज्ञान से कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में हमें नेहरू युग की नीतियों पर गौर करने की आवश्यकता है, जब स्वतंत्रता के बाद के संकट-काल में औपनिवेशिक शोषण, द्वितीय विश्व युद्ध और विभाजन से तबाह हुई अर्थव्यवस्था में कुछ हद तक व्यवस्था प्राप्त करने की आवश्यकता थी। अर्थव्यवस्था, नियोजित विकास और मिश्रित अर्थव्यवस्था की कमान संभालने वाले नेहरूवादी सिद्धांत पर बहुत चर्चा और टिप्पणी की गई है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में गुटनिरपेक्षता की नीति के आर्थिक और विकास पहलू के बारे में बहुत कम कहा गया है, जिसका नेहरू ने समर्थन किया था। अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में हमारी स्वतंत्रता से पहले और बाद में राजनीतिक परिदृश्य पर अपना दबदबा बनाए रखा। 1942 से 1962 तक 20 वर्षों तक वे राष्ट्रीय नीतियों के सभी पहलुओं, विशेषकर देश की विदेश नीति के पूर्ण नियंत्रण में थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया दो प्रतिद्वंद्वी शक्ति ब्लॉकों में विभाजित हो गई और उपनिवेशवाद का युग समाप्त हो गया, तो एशिया और अफ्रीका के देशों को अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी ब्लॉक जिसे प्रथम विश्व कहा जाता था और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले समाजवादी ब्लॉक जिसे द्वितीय विश्व कहा जाता था, के बीच चयन करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जो कि मूलतः नव-उपनिवेशवाद था,

आर्थिक संकट का सामना

भारत गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। क्या हमें नेहरू की नीतियों पर विचार करना चाहिए? यह लेख इस बात पर जोर देता है कि हमें अतीत के अनुभवों से कैसे सीख लेनी चाहिए।

नेहरू ने अफ्रीकी-एशियाई देशों को एक स्वतंत्र पथ पर ले जाया, जिसे गुटनिरपेक्ष तीसरी दुनिया कहा जाता था। विश्व युद्ध की भयावहता से उबरने वाली दुनिया में यह कम ही महसूस किया गया कि गुटनिरपेक्षता की नीति

तीसरी दुनिया के देशों के गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने 1950 के दशक में अपनी शुरुआत के बाद आने वाले तीन दशकों में बड़ी प्रगति की। शायद मानव इतिहास में कभी भी कमज़ोर और वंचित राष्ट्र शक्तिशाली और विशेषाधिकार प्राप्त राष्ट्रों द्वारा आरक्षण, विरोध और यहाँ तक कि खुली दुश्मनी के सामने विश्व शक्ति नहीं बन पाए।

वर्ष 1983 में नई दिल्ली में आयोजित सातवां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन शायद गुटनिरपेक्ष आंदोलन का चरम बिन्दु था। नेहरू और नासिर जैसे संस्थापक नेताओं के चले जाने के बाद इस बात के स्पष्ट संकेत मिल रहे थे कि आंदोलन की भावना के प्रति कई सदस्यों की प्रतिबद्धता डगमगा रही है। अगले 10 वर्षों में दुनिया में बिगड़ती आर्थिक स्थिति और 1991 में सोवियत संघ के पतन ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के भाग्य को सील कर दिया। अब हम इसके उद्देश्य और प्रासंगिकता को पूरी तरह से भूल चुके हैं, हालांकि हम अभी भी इसके संस्थापकों द्वारा हमारे सामने रखे गए उद्देश्यों का पीछा कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों ने भारत को मुक्त उद्यम और

कॉर्पोरेट अर्थव्यवस्था के मार्ग पर डाल दिया। हालांकि सरकार द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था और स्वतंत्र विदेश नीति के शासन के अंत में कोई परस्पर संघर्ष नहीं था, लेकिन इसे गुटनिरपेक्षता की नीति के अंत के रूप में देखा गया। नेहरू और जिसे गांधी-नेहरू वंश कहा जाता है, के प्रति राजनीतिक विरोध ने भी नेहरू की विदेश नीति के सिद्धांतों के विरोध का माहौल पैदा किया।

अब विकास के वर्तमान मोड़ पर भारत खुद को एक कठोर दुनिया में अकेला पाता है, जिसमें उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं है और उसे खुद ही अपना विकास करना है। कई अन्य देशों, खासकर दक्षिण अमेरिका के साथ भी यही स्थिति है। लैटिन अमेरिका में मजबूत आवाजें सुनी जा रही हैं जो आर्थिक विकास और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संबंधों के अमेरिकी नेतृत्व वाले मॉडल को खारिज करते हुए पूर्व-वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था की दुनिया में लौटने की मांग कर रही हैं।

प्रश्न यह है कि क्या नेहरूवादी नीतियों, विशेषकर गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है, जो बड़ी शक्तियों के इरादों से प्रभावित हुए बिना आर्थिक विकास के पैटर्न का नुस्खा था।

गुटनिरपेक्षता का महत्व

नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति ने कैसे देशों को एक स्वतंत्र पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया? जानिए कैसे यह नीति आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है।

इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें गुटनिरपेक्षता की नीति के मूल सिद्धांतों पर पुनः विचार करना होगा।

1950 के दशक में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत, युद्ध के तुरंत बाद की दुनिया में नव-स्वतंत्र तीसरी दुनिया के देशों के लिए एक आवश्यकता थी, क्योंकि उनके सामने बहुत सी समस्याएँ थीं, जो मुख्य रूप से बिगड़ते आर्थिक संकट और व्यापक जनसमूह के जीवन को बेहतर बनाने की ज़रूरत के कारण थीं। विकासशील देशों को चुनौती का सामना करने के लिए एक नई जागरूकता और एक नई प्रतिबद्धता की आवश्यकता थी। अब जब हम कोरोना महामारी के कारण एक बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, तो हमारे वर्तमान नेताओं को उसी प्रतिबद्धता, राजनीतिज्ञता, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता की आवश्यकता है, जो उनके पूर्वजों ने पचास और साठ के दशक में दिखाई थी। जब तक उपनिवेशवाद के तुरंत बाद के युग की प्रेरक शक्ति को पुनर्जीवित नहीं किया जाता, तब तक विकासशील दुनिया के अधिकांश देशों को आने वाले समय में आने वाली चुनौतियों का सामना करना मुश्किल होगा।

आइए याद करें कि शायद मानव इतिहास में कभी भी कुछ कमज़ोर और वंचित राष्ट्रों की एक छोटी सी पहल दुनिया के शक्तिशाली और विशेषाधिकार प्राप्त राष्ट्रों द्वारा आरक्षण, विरोध और यहां तक कि खुले शत्रुता के सामने एक विश्व शक्ति नहीं बन पाई। मानव इतिहास सम्राटों के कारनामों का लेखा-जोखा है जिन्होंने दूसरों को अपने हुक्म चलाने के लिए मजबूर किया। यह कमज़ोरों पर शक्तिशाली लोगों की विजय की गाथा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इस सदियों पुराने पैटर्न का विरोधी था। यह उस ऐतिहासिक प्रक्रिया की अवहेलना थी जिसने अस्तित्व के तथ्य के रूप में कुछ लोगों के ऊपर दूसरों के वर्चस्व को निर्धारित किया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन मनुष्यों की अपनी पहचान और स्वतंत्रता को बनाए रखने और इस तथ्य से बेपरवाह होकर कि वे ऊंचे या नीचे, बड़े या छोटे, मजबूत या कमजोर हैं, की जन्मजात इच्छा की अभिव्यक्ति थी। यह उस चीज़ की सबसे शक्तिशाली और स्पष्ट अभिव्यक्ति थी जिसे मनुष्य हमेशा से जानता था लेकिन राज्य-कौशल के रूप में शायद ही कभी अभ्यास कर पाया कि मानव आत्मा को बांधा नहीं जा सकता और लोगों की अपनी नियति तय करने की इच्छाओं का सम्मान किया जाना चाहिए।

विकास की चुनौती

क्या वर्तमान पीढ़ी के नेता गरीबों के हितों का ध्यान रख रहे हैं? इस लेख में विकास और सामाजिक संवेदनशीलता के बीच के महत्वपूर्ण संतुलन पर चर्चा की गई है।

उभरते एशिया के नेहरू, अफ्रीका की हलचल के नासिर और भौतिकवाद की मूर्खता से अवगत यूरोप के टीटो ने उत्तर-औपनिवेशिक समाजों के अन्य नेताओं के साथ मिलकर अपने नव-स्वतंत्र देशों के लिए एक ऐसा मार्ग तैयार करने का प्रयास किया, जिसके द्वारा ये देश किसी भी महाशक्ति गुट में शामिल होने के विकल्प को शुरू से ही अस्वीकार कर सकें। गुटनिरपेक्षता अनिवार्य रूप से एक गैर-गुट आंदोलन के रूप में विकसित हुई। लेकिन इससे

भी अधिक यह एक शांति आंदोलन था, एक ऐसा आंदोलन जो विकास के लिए दुनिया की ऊर्जा और संसाधनों को संरक्षित करने की इच्छा से पैदा हुआ था ताकि सदियों से औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा व्यवस्थित रूप से लूटे गए विश्व में बेहद खराब जीवन स्थितियों में सुधार हो सके। अपने लुप्त होने के लगभग 30 वर्षों के बाद आज विकासशील दुनिया का नेतृत्व नेताओं की एक ऐसी पीढ़ी कर रही है जो गरीबी से लड़ने और विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए और भी अधिक प्रतिबद्ध है। वे अपनी कमियों के प्रति उतने ही संवेदनशील हैं, जितना कि इस तथ्य के प्रति कि दुनिया के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया उनके जीवनकाल में गरीबी, कुपोषण, बीमारी और बेरोजगारी के अभिशाप को दूर करने के लिए बहुत धीमी रही है। उनकी अधीरता छिपी नहीं है। ये नेता अपनी-अपनी राष्ट्रीय परंपराओं में डूबे हुए हैं। वे कई मायनों में एक-दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मूलतः वे एक गौरवान्वित समूह हैं। इन नेताओं ने पिछले दशकों की वास्तविक राजनीति देखी है। वे यह भी जानते हैं कि उन्हें अपने-अपने देशों के हितों की ईर्ष्यापूर्वक रक्षा करनी चाहिए, बजाय इसके कि वे विकसित देशों की देखभाल में लग जाएं, जिनके प्रस्ताव और नुस्खे विभिन्न मंचों पर उनके देशों के विकास के लिए उन्हें निरंतर शोषण करने की इच्छा की स्पष्ट अभिव्यक्ति हैं, बेशक, बहुत अधिक सूक्ष्म तरीके से।

हालाँकि, विकासशील दुनिया में नेताओं की वर्तमान पीढ़ी बुनियादी आदमी और औरत के लिए उतनी संवेदनशीलता नहीं दिखाती है - सबसे गरीब लोग जिन्हें मदद की सबसे अधिक ज़रूरत है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की जटिलताओं ने उन्हें भ्रमित कर दिया है और नेतृत्व, चाहे लोकतांत्रिक हो या अधिनायकवादी, जनता के साथ बढ़ते अलगाव से पीड़ित हैं। वे इस बुनियादी मुद्दे को दरकिनार कर देते हैं कि क्या विकास कार्य उनके देशों में बुनियादी आदमी और औरत को संबोधित है। उन्हें महात्मा गांधी द्वारा निर्धारित अग्नि परीक्षा लेने की आवश्यकता है जिन्होंने कहा था। "आप जो भी करें, पहले खुद से पूछें कि क्या यह गरीबों और दलितों की मदद करने वाला है।"

नव-उपनिवेशवाद का विरोध

गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने कैसे नव-उपनिवेशवाद के खिलाफ एक आवाज उठाई? यह लेख हमें याद दिलाता है कि कमजोर राष्ट्र भी शक्तिशाली बन सकते हैं।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जैसा कि इसके संस्थापक पिताओं ने कल्पना की थी, अनिवार्य रूप से एक जन आंदोलन था - दुनिया के गरीबों का आंदोलन जो उपनिवेशवाद के शिकार रहे हैं और जो आधुनिक दुनिया में विकसित देशों के नागरिकों के साथ समान भागीदार बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन था। इसलिए, अनिवार्य रूप से मानव जाति के दो-तिहाई लोगों की बढ़ती आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति। हालाँकि, जैसा कि नेहरू ने सितंबर 1960 में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में कहा था कि शांति सुनिश्चित किए बिना कोई विकास नहीं हो सकता। इसलिए, शांति के लिए यह संघर्ष वैसा ही बना हुआ है, जैसा कि युद्ध के तुरंत बाद के युग में था।

नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति पर पुनर्विचार करने से हमें अपने देशों के साथ-साथ एशिया और अफ्रीका के सभी विकासशील देशों की विकास रणनीतियों के बारे में एक बहुत ही सही परिप्रेक्ष्य मिल सकता है, जिन्हें अपने लोगों को अच्छे जीवन की बुनियादी झलक देने के संघर्ष में अभी लंबा रास्ता तय करना है।

नेहरू द्वारा परिभाषित गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मूल भावना शांति, महाशक्तियों पर न्यूनतम निर्भरता के साथ विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग, प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल विकास पैटर्न और समावेशी विकास रणनीतियां थीं ताकि विकास का लाभ हर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन की यह भावना आज भी न केवल प्रासंगिक है बल्कि इसे आत्मसात करना भी आवश्यक है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था के "अर्थवाद" ने जन-केंद्रित विकास संस्कृति की भावना को दबा दिया है और हमें जल्दी अमीर बनने के मॉडल की दौड़ में शामिल कर दिया है जो पश्चिमी संस्कृति का अभिशाप है।

यह निश्चित रूप से भारत जैसी प्राचीन सभ्यता की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए सही मॉडल नहीं है।

****

लेखक : मीडिया मैप के मुख्य सह संपादक है

ऑनलाइन शिक्षा के तरीको में सुधार की आवश्यकता

डॉ. अनुभव माथुर

भारत की शिक्षा व्यवस्था में लगभग 25 करोड़ छात्र स्कूलों में और 3.7 करोड़ कॉलेजों तथा व्यावसायिक संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा तंत्रों में से एक बनाता है। हालांकि, इस विशाल संख्या के बावजूद, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 30% छात्र ही इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की सुविधा का लाभ उठा पा रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान, लॉकडाउन और संक्रमण के डर से स्कूल और कॉलेज बंद रहे, जिससे 70% छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई, जो किसी विकासशील देश के लिए एक गंभीर स्थिति है जहाँ शिक्षा पिछड़ेपन को मिटाने का एक प्रमुख साधन है।

महामारी ने यह भी स्पष्ट किया कि इंटरनेट और उपकरणों की सुविधा वाले छात्रों का छोटा प्रतिशत भी पूरी तरह से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सका। इसका मुख्य कारण केवल इंटरनेट की खराब कनेक्टिविटी और अनियमित बिजली आपूर्ति ही नहीं था, बल्कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए आवश्यक डिजिटल कौशल और शिक्षकों का प्रशिक्षण भी प्रमुख समस्याएँ थीं। अधिकांश शिक्षक डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने में दक्ष नहीं थे, जिससे ऑनलाइन शिक्षा प्रक्रिया में रुकावटें आईं। यह स्थिति दर्शाती है कि डिजिटल कौशल को बेहतर बनाना वर्तमान समय की एक आवश्यकता बन गया है।

डिजिटल मीडिया का उपयोग आज के शिक्षण तंत्र को एक नई दिशा में ले जा रहा है। यह न केवल शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद को आसान बना सकता है, बल्कि उनके संचार को अधिक प्रभावी भी बना सकता है। डिजिटल मीडिया के माध्यम से जानकारी वेबसाइटों, ऐप्स, सॉफ्टवेयर, वीडियो गेम आदि के माध्यम से प्रसारित की जा सकती है, जिससे शिक्षा की पहुँच अधिक व्यापक और सुलभ बनती है। लेकिन इसके लिए शिक्षकों और छात्रों दोनों को डिजिटल उपकरणों और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर काम करने का बुनियादी ज्ञान होना जरूरी है।

> भारत के शिक्षा तंत्र में डिजिटल शिक्षा का महत्व तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन डिजिटल संसाधनों की कमी और कौशल के अभाव ने इसे चुनौतीपूर्ण बना दिया है। महामारी के दौरान शिक्षा में डिजिटल संसाधनों का उपयोग अनिवार्य हो गया, परन्तु इसकी सफलता के लिए शिक्षकों और छात्रों में डिजिटल कौशल की कमी प्रमुख बाधा बनी। डिजिटल शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए लचीले डिजिटल मीडिया कार्यक्रम, औपचारिक पाठ्यक्रम, और डेटा साझाकरण प्रणाली की आवश्यकता है।

डिजिटल शिक्षा को और अधिक कुशल बनाने के लिए शिक्षकों को विभिन्न तकनीकों का कम से कम एक कार्यात्मक ज्ञान होना आवश्यक है। इससे वे छात्रों के साथ बेहतर संवाद कर सकेंगे और डिजिटल उपकरणों का प्रभावी उपयोग कर पाएंगे। ऐसा करने से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और परिवर्तन के अवसर भी खुलते हैं। डिजिटल मीडिया का उपयोग न केवल समय और दूरी की बाधाओं को दूर करता है, बल्कि शिक्षा की पहुँच को भी बढ़ा सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से डेटा साझा करना और उसे सुलभ रखना जानकारी के प्रसार को भी सुगम बनाता है।

हालाँकि, भारत में डिजिटल शिक्षा के लिए एक मानक मॉडल अभी विकसित हो रहा है। शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत लोगों को इसे अपनाने और अपने कौशल को उन्नत करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करने होंगे। इस दिशा में, शिक्षण समुदाय को डिजिटल मीडिया की बुनियादी समझ और आईटी कौशल के लिए प्रशिक्षित करना आवश्यक है, ताकि ऑनलाइन शिक्षा को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

डिजिटल शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए तीन-सूत्रीय रणनीति अपनाई जा सकती है:

1. लचीले और बहु-आयामी डिजिटल मीडिया कार्यक्रम** - जिसमें संकाय के आईटी और डिजिटल कौशल संवर्धन को प्राथमिकता दी जाए।

2. एक औपचारिक डिजिटल मीडिया पाठ्यक्रम का विकास** - ताकि शिक्षा के क्षेत्र में एक सार्वभौमिक अनुप्रयोग सुनिश्चित किया जा सके।

3. खुले डेटा प्रणाली का नेटवर्क** - जो शिक्षा क्षेत्र में समस्या समाधान में सहयोग और सहभागिता को बढ़ावा दे।

कोरोना संकट के दौरान ऑनलाइन शिक्षा एक अनिवार्य उपाय बन गई थी, लेकिन अब इसे शिक्षा के दायरे को विस्तारित करने के एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। महामारी के बाद, ऑनलाइन शिक्षा को केवल कठिन परिस्थितियों का

समाधान नहीं बल्कि शिक्षा प्रणाली को उन्नत बनाने के माध्यम के रूप में भी अपनाया जाना चाहिए।।

****

लेखक :बेनेट यूनिवर्सिटी नॉएडा में एसोसिएट प्रोफेसर है।

क्या ऑनलाइन पढ़ाई मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है?

अमिताभ श्रीवास्तव

कोरोना महामारी के दौरान बच्चों के जीवन और शिक्षा को बाधित होने से बचाने के लिए कई उपाय किए गए। इनमें से एक था ऑनलाइन पढ़ाई, जिससे बच्चों को संक्रमण के डर के चलते स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि, अब वही ऑनलाइन पढ़ाई और स्मार्टफोन पर बढ़ती निर्भरता बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल रही है। बच्चों के स्मार्टफोन उपयोग के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अब इसे सीमित करने के लिए कई देशों में जागरूकता बढ़ाई जा रही है।

कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गई थी। छोटे बच्चों से लेकर नर्सरी तक के बच्चों को भी ऑनलाइन कक्षाओं में हिस्सा लेना पड़ा। इससे माता-पिता और शिक्षकों पर भी दबाव बढ़ा। मेरे निजी अनुभव में, मेरी पोती की कक्षा में शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चों का ध्यान बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। एक शिक्षक ने एक बार एक बच्चे से केले का नाम पूछा, लेकिन वह बच्चा अपनी नींद से जागकर संतरा बोल गया। इस प्रकार के घटनाक्रमों ने दिखाया कि ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों का ध्यान भटक रहा था और उनकी पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था।

कोरोना के बाद जब स्कूल फिर से खुले, तो ऑनलाइन पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों के बीच स्मार्टफोन का इस्तेमाल भी बढ़ गया। अब इसे लेकर दुनियाभर में चिंता बढ़ रही है कि स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग का बच्चों पर गहरा असर हो रहा है। ब्रिटेन में डेजी ग्रीनवेल और क्लेयर फर्नीहॉफ द्वारा फरवरी में शुरू किए गए 'स्मार्टफोन फ्री चाइल्डहुड' नामक एक अभियान ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की, जिसमें कुछ ही हफ्तों में 60,000 से अधिक सदस्य जुड़े। इसका उद्देश्य बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखना और उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना है।

ब्रिटेन के सरकारी नियामक ऑफकॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार, 12 साल की उम्र तक आते-आते 97% बच्चों के पास स्मार्टफोन होता है। अमेरिका में, 10 साल की उम्र में 42% और 14 साल तक 91% बच्चों के पास स्मार्टफोन होते हैं। माता-पिता बच्चों को मनोरंजन के लिए और उनसे जुड़े रहने के उद्देश्य से स्मार्टफोन दे रहे हैं। हालांकि, इसके साथ ही सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग और संभावित मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ भी बढ़ रही हैं।

स्मार्टफोन का उपयोग बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। एक अध्ययन के अनुसार, जो बच्चे छोटी उम्र में स्मार्टफोन का उपयोग शुरू करते हैं, उनमें मानसिक समस्याओं की संभावना अधिक होती है। रिपोर्ट में पाया गया कि 6 साल की उम्र में पहला स्मार्टफोन पाने वाले बच्चों में मानसिक तनाव अधिक देखा गया, जबकि 15 साल की उम्र में स्मार्टफोन लेने वाले बच्चों में तनाव और मानसिक समस्याएँ कम थीं। यह निष्कर्ष बताता है कि स्मार्टफोन के उपयोग में देरी करने से बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रह सकता है। 'द एंग्जियस जेनरेशन' के प्रमुख शोधकर्ता ज़ैक रौश का मानना है कि स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग बच्चों के लिए हानिकारक है।

उन्होंने कहा कि माता-पिता अपने बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखने के लिए अधिक जागरूक हो रहे हैं। यह स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का संयोजन है, जो बच्चों के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। सोशल मीडिया के निरंतर उपयोग से बच्चों में आत्म-सम्मान की कमी, अवसाद और शारीरिक छवि से असंतोष जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अन्य कई देशों में इस विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए कई संगठन काम कर रहे हैं। 'वेट अनटिल 8थ' नामक ऑस्टिन स्थित एक संगठन बच्चों के स्मार्टफोन उपयोग को सीमित करने का समर्थन कर रहा है। कनाडा में 'अनप्लग्ड' और ऑस्ट्रेलिया में 'हेड्स अप अलायंस' जैसे संगठन भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। ब्रिटेन की सरकार ने भी स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अमेरिका के कुछ राज्यों में भी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन उपायों का उद्देश्य बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना और उन्हें स्क्रीन टाइम से दूर रखना है।

स्मार्टफोन बच्चों की पढ़ाई में सहायक हो सकता है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। माता-पिता और समाज को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को स्मार्टफोन का संयमित उपयोग करने दिया जाए।

बच्चों के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए उन्हें अधिक समय तक स्मार्टफोन से दूर रखने के प्रयास किए जाने चाहिए। वर्तमान में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को संरक्षित रखना एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई है, और इसके लिए हमें एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है ताकि हम बच्चों को एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन दे सकें।

****

लेखक : वरिष्ठ पत्रकार है।

'प्रयास' के जुगनुओं की उड़ान

अमिताभ श्रीवास्तव

जुगनुओं को लेकर रात रोशन कीजिये

सूरज के इंतज़ार में सहर हो जायेगी

(राहत इंदोरी)

मुझे जुगनुओं से शुरू से ही एक अजीब सा लगाव रहा है जब मैं बचपन में पूसा इन्स्टिटूट में रहता था।

बारिश के मौसम में मैं अपनी छोटी बहन के साथ दूर पेड़ों के बीच घूमता हुआ जुगनू ढूंढ़ता था और पकड़ कर अपनी शर्ट की जेब में रख लेता था।

ये तो बहुत बाद में, बल्कि बुढ़ापे में, समझ आया की जुगनुओं की एक विशिष्ट पहचान होती है जो उन्हें चांद सितारों से ऊंचा स्थान देती है।उन्हें चमकने के लिए किसी सूरज या चांद की रोशनी नहीं चाहिए। वो अपनी रोशनी खुद साथ लेकर चलने हैं छोटी सी सही लेकिन बिल्कुल आत्मनिर्भर।

भारत की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था 'प्रयास' लगभग 36 वर्षों से समाज से ठुकराए और तिरस्कृत बच्चों के उत्थान और उनके पुनर्वास के लिए देश के 12 राज्यों में उनके हक की लड़ाई लड़ रही है ऐसे ही ना जाने कितने जुगनुओं की उड़ान की साक्षी है।

जून 1988 में दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में लगी एक आग में सैकड़ों बच्चों के आशियाने जल गये और बहुत से बच्चे यतीम हो गये।हादसे के बाद दिल्ली के बड़े बड़े अफसर मौके पर गये और लौट गये लेकिन अमोद कंठ जो उस समय दिल्ली पुलिस में वरिष्ठ पद पर थे के मन को उन बच्चों को देखकर बहुत आघात हुआ और उन्होंने फैसला कर लिया कि इन बच्चों के लिए कुछ करना है और इस तरह एक छोटे से कमरे में प्रयास की स्थापना हुई जो आज एक वट वृक्ष की तरह देश के 12 राज्यों में फ़ैल कर बेसहारा और तिरस्कृत बच्चों को शरण देकर उन्हें फिर से जीने का, अपने पंख फैलाने का अवसर दे रहा है।

नीचे दिए गए चन्द उदाहरण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हर बच्चे में उडने की क्षमता है अगर उसके पंख कुतरे ना जायें।

जुगनुओं का संदेश

जीवन में जुगनू की तरह आत्मनिर्भरता का महत्व समझें। ये छोटे जीव हमें सिखाते हैं कि अंधेरे में भी रोशनी खुद उत्पन्न की जा सकती है।

सभी बच्चों की पहचान छुपाने के लिए उनके और उनके शहर के नाम नहीं दिए जा रहे हैं।

जुगनू १

सारा की दुखद कहानी मानव तस्करी की कठोर वास्तविकताओं और कमजोर समुदायों के भीतर शोषण के गंभीर परिणामों की परिचायक है। उसके पिता का बचपन में निधन हो गया और वह अपनी माँ और बहन के साथ रहती थी। एक दिन उसकी अपनी सगी माँ ने हताशा या किन्हीं अन्य कारणों से अपनी बेटी को एक अजनबी को 55,000 रुपये की मामूली राशि में बेचने का कठोर निर्णय ले लिया। मानवता और बचपन के समस्त अधिकारों के इस घोर उल्लंघन ने न केवल सारा से उसका बचपन छीन लिया, बल्कि उसे अकल्पनीय कठिनाई और अनिश्चितता के जीवन के अधीन कर दिया। इस अमानवीय कृत्य ने उसे शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार के साथ-साथ जबरन श्रम और शोषण के नर्क में ढकेल दिया।

सारा की दुखद कथा उस समय और भी गंभीर मोड़ लेती है क्योंकि वह उस खरीदार के हाथों यौन शोषण और शोषण का शिकार हो जाती है जिसे उसे बेच दिया गया था। अकथनीय क्रूरता के बीच, सारा ने न केवल अपनी माँ के विश्वासघात को सहन किया, बल्कि एक इंसाननुमा जानवर के जघन्य कार्यों को भी सहन किया, जो उसे केवल एक वस्तु के रूप में देखता था। सारा पर किए गए दुर्व्यवहार और शोषण के आघात ने एक ऐसा चक्र रचा, जिससे न केवल उसका बचपन, बल्कि उसके बुनियादी मानवाधिकार भी छीन लिए।

फिर एक दिन वह एक डिलीवरी बॉय की मदद से उस जगह से भाग गई जहां उसे बंदी बनाया गया था। उसकी जिंदगी में एक दयालु महिला आई जिसने सारा को उसके घर पर रहने की अनुमति दी। उसने महिला को सब कुछ बताया और महिला ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में उसकी मदद की। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सी. डब्ल्यू. सी.) के निर्देश से, वह वर्तमान में लड़कियों के लिए प्रयास बाल गृह में रह रही हैं।

प्रयास ने उसके जीवन में इस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान उसका समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका

निभाई। संस्था ने सुनिश्चित किया कि उसकी सभी ज़रूरतें पूरी हों, जिनमें चिकित्सा देखभाल, कानूनी सहायता, परामर्श, आश्रय, भोजन और कपड़े शामिल हैं। अदालत ने इसे 5 लाख अंतरिम अंतरिम मुआवजे का आदेश दिया है। उसको कुल 12 लाख रुपये दिए जाएंगे। वकालत के माध्यम से वह अब सुधार के रास्ते पर है और वित्तीय मुआवजे के साथ उसके भविष्य की स्थिरता भी निर्धारित है।

प्रयास का सफर

'प्रयास' संस्था की 36 वर्षों की यात्रा ने हजारों बेसहारा बच्चों को नई जिंदगी दी है। यह संस्थान तिरस्कृत बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है।

सारा की कहानी समाज के सबसे कमजोर वर्गों की रक्षा करने और मानव तस्करी और शोषण को खत्म करने के लिए एक सामूहिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने की एक मार्मिक दास्तां के रूप में देखी जा सकती है।

जुगनू 2

मिमी एक युवा लड़की है जिसे भयानक चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब उसकी माँ का उस समय निधन हो गया जब वह मात्र 9 साल की थी। अपने पिता और तीन भाई-बहनों के साथ रहते हुए, मिमी ने जबरदस्त भावनात्मक उथल-पुथल की यात्रा शुरू की।

मिमी ने बचपन से ही यौन शोषण झेलना शुरू कर दिया। उसने जो आघात झेला, उसने न केवल दिखाई देने वाले शारीरिक निशान छोड़े, बल्कि गहरे भावनात्मक घाव भी छोड़े। जब वह 13 साल की थी, तब वह अपने छोटे भाई के साथ नाश्ता खरीदने के लिए पास की एक दुकान पर गई। घर लौटते समय एक आदमी ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। जब वे अंदर गए तो उस आदमी ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया और उसका यौन उत्पीड़न किया। इसके बाद वह थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब वह सलाखों के पीछे है।

अपने पिता के वित्तीय संघर्ष के कारण, मिमी, अपनी दो बहनों के साथ बाल कल्याण समिति के आदेश से लड़कियों के प्रयास बाल गृह में रह रही है (CWC और समर्पित पेशेवरों के समर्थन से मिमी ने सीसीआई के भीतर अपने जीवन यात्रा शुरू की।

प्रयास ने पूरी कानूनी कार्यवाही में उसकी सहायता की, जिसके परिणामस्वरूप जिला अदालत ने अपराधी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। उसे अदालत के आदेश से 5 लाख मुवावजा मिला है। उसके पुनर्वास के लिए उसे प्रयास द्वारा प्रस्तावित सिलाई पाठ्यक्रम में नामांकित किया गया, जिससे उन्हें कपड़ा उद्योग में रोजगार मिला। उसके असाधारण प्रदर्शन ने उसे उसके कौशल और उपलब्धियों को मान्यता देते हुए कपड़ा मंत्रालय (जी. ओ. आई.) से एक प्रमाण पत्र भी मिला।

सभी के सहयोगात्मक प्रयासों से मिमी दुश्कर्मों के चक्र से बचने में सफल हुई और उसे लड़कियों के प्रयास बाल गृह में नये जीवन की आशा मिली।

जुगनू 3

दिल्ली की भीड़भाड़ वाली गलियों की भूलभुलैया में, 12 वर्षीय लिसा ने खुद को शारीरिक और यौन शोषण की कठोर वास्तविकताओं में बुरी तरह फंसा पाया। एक बीमार माँ और एक उदासीन पिता के साथ, उसे घर में कभी चैन नहीं मिला। जिम्मेदारी का भार उसके छोटे कंधों पर बहुत अधिक था, जो उसके बचपन पर भारी पड़ गया।

जैसे जैसे उसकी माँ की तबियत बिगड़ने लगी और उसके पिता दूरी बनाने लगे लिसा ने शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों की गुमनामी में अपने आप को खो दिया। बाजारों में हॉर्न का शोर उनकी एकांत यात्रा की पृष्ठभूमि बन गई, एक ऐसी यात्रा जो शारीरिक शोषण से बचने की आवश्यकता से प्रेरित थी।

घर पर उसकी असहज स्थिति का लाभ उठाते हुए, उसकी माँ के दोस्तों में से एक ने उसे वेश्यावृत्ति का प्रलोभन दिया। उस महिला ने उसे धमकी दी कि वह किसी को कुछ न बताए अन्यथा...। 12 साल की छोटी उम्र से उस पर तरह तरह के अत्याचार होते रहे और उसे बचने का कोई रास्ता नहीं मिला। वह नहीं जानती थी कि किससे संपर्क करना है या क्या करना है। एक दिन वह इन जुर्मों से तंग आकर घर से भाग गई और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के पास पहुंच गई और समुचित परामर्श के बाद, उसने खुलासा किया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। तब से वह लड़कियों के प्रयास बाल गृह में रह रही है और अनौपचारिक

मिमी का साहस

मिमी ने कठिनाइयों का सामना करते हुए खुद को मजबूत बनाया। अब वह सिलाई सीखकर अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ा रही है।

शिक्षा में भाग ले रही है। उसने चित्रकला और चित्रकारी में भी रुचि दिखाई है।

जब वह पहली बार प्रयास आई, तो वह अपने अनुभवों का खुलासा करने में संकोच कर रही थी। लेकिन लगातार प्रयासों और परामर्श के माध्यम से, उसने अंततः खुलकर अपनी कहानी साझा की। प्रयास उसे चिकित्सा, देखभाल,आश्रय, भोजन और कपड़ों जैसी उसकी सभी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने का दायित्व लिया । अब प्रयास उसके मुआवजे की प्रक्रिया में है ताकि वह उस वित्तीय सहायता को प्राप्त कर सके जिसकी वह हकदार है। उसे औपचारिक विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए भी तैयारी हो रही है।

हर कदम के साथ, वह एक अलग जीवन के सपने पूरे करने में सक्षम होने लगी है और यौन शोषण के दुर्दिनों से बाहर निकलने में बहुत हद तक सफल हो गई है ।

अपरिचित चेहरों के बीच, उसे एक अस्थायी परिवार मिला-एक समर्थन प्रणाली जिसने उसकी नाजुक उम्मीदों को जन्म दिया। जैसे-जैसे लिसा की कहानी सामने आई, यह मानव के संघर्ष का एक मार्मिक वसीयतनामा बन गया। उपेक्षा और शोषण की गहराई से, वह एक दृढ़ निश्चयी फीनिक्स की तरह उभरी और उस चक्र से मुक्त होने में सफ़ल हुई जिसने उसके अस्तित्व को परिभाषित करने की कोशिश की थी। दिल्ली, जो कभी कठिनाइयों का शहर था, लिसा के कायाकल्प की पृष्ठभूमि में बदल गया-एक ऐसी जगह जहाँ एक लड़की अपने चुराए गये बचपन को फिर से हासिल करने की ताकत की खोज मे सफल रही।

जुगनू 4

दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर, 17 वर्षीय अवनि ने गरीबी की छाया में जीवन की चुनौतियों का सामना किया। उसके दिन सपनों और जीवित रहने के बीच एक नाजुक संतुलन थे, जो कठिनाई के धागे से बुने हुए थे। उसकी आशावादी आँखों के पीछे एक दर्दनाक वास्तविकता के निशान छिपे हुए थे-अपने ही घर में शारीरिक शोषण के क्रूर हाथों का शिकार।

उसकी मा किसी अन्य पुरुष के साथ भाग गई और उसके पिता ने भी दूसरी महिला से शादी कर ली।

अपनी परिस्थितियों के बोझ के बावजूद, अवनि की आत्मा ने हार नहीं मानी। हर दिन, वह अपने मन के छिपे हुए कोनों में शरण मांगती थी, जहाँ एक बंजर परिदृश्य में एक बेहतर भविष्य के सपने रंगीन फूलों की तरह खिलते थे। धूल भरी सड़कें उसकी शरण बन गईं, और शहर का शोर वह धुन बन गई जिस पर वह प्रतिकूल परिस्थितियों में नृत्य करती थी।

समाज की जिम्मेदारी

'प्रयास' बच्चों की सुरक्षा और मानव तस्करी के खिलाफ सामूहिक संघर्ष का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी की जिम्मेदारी है।

शांति की खोज ने उसे मादक द्रव्यों के सेवन की खतरनाक अंधेरों में धकेल दिया, क्योंकि वह अपने उथल-पुथल भरे पारिवारिक वातावरण से हुए भावनात्मक घावों से बचने की कोशिश कर रही थी। मादक द्रव्यों के दुरुपयोग ने उसे जीवन की कठोर वास्तविकताओं से एक क्षणिक राहत तो जरूर प्रदान की, लेकिन जिसके दूरगामी परिणाम घातक थे।

एक दिन, पार्क में एक अजनबी द्वारा उसका यौन शोषण किया गया और पुलिस को वह दयनीय अवस्था में मिली। इसके बाद उसे बाल कल्याण समिति के आदेश पर लड़कियों के प्रयास बाल गृह में रखा गया (CWC). हालांकि, कुछ हफ्तों के बाद, उसे ड्रग्स छोड़ने के दुष्परिणामो का अनुभव होने लगा, जैसे बेचैनी, अनिद्रा, क्रोध और कई अन्य समस्याएं पैदा हुईं। इसलिए, उसे बेहतर देखभाल के लिए नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया। धीरे-धीरे, उनकी हालत में सुधार होने लगा और फिर उसे सी. सी. आई. की देखरेख में रखा गया। वर्तमान में, वह उस संगठन में अनौपचारिक शिक्षा में भाग लेती है जहाँ वह रह रही है और उसे चित्रकला और नृत्य अच्छा लगता है।

प्रयास ने चिकित्सा देखभाल, कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक सहायता जैसे समन्वित हस्तक्षेपों की एक श्रृंखला के माध्यम से उसका इस लड़ाई में समर्थन दिया है।

प्रयास ने अदालती कार्यवाही के माध्यम से उसका समर्थन किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी आवाज सुनी जाए और उसके अधिकारों की रक्षा की जाए। अदालत की कार्यवाही पूरी हो चुकी है, और अदालत ने उसे Rs. 2.5 लाख के मुआवजे का आदेश दिया है। बस इस प्रक्रिया के अंतिम चरण में उसके खाते में राशि जमा करने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन को पूरा करना बाकी है। इस व्यापक समर्थन के कारण वह अब बहुत बेहतर मानसिक और शारीरिक स्थिति में है।

उसकी त्वचा पर निशान उसके भयानक अतीत की कहानी बताते थे, लेकिन उसकी लड़ने की अटूट भावना ने उसका वर्तमान बदल दिया। दिल्ली के दिल में, अवनि नाम की एक लड़की ने आखिर अपनी जीवन गाथा फिर से लिखने की ताकत पाई।

****

लेखक : वरिष्ठ पत्रकार है।

तेज रफ्तार ले रही है हजारों लोगों की जान

डॉ मुजफ्फर हुसैन ग़ज़ाली

हर दिन दैनिक समाचार पत्र सड़क दुर्घटना की कई खबरें लेकर आता है। दुर्घटना में किसी की जान जाती है, कोई जीवन भर के लिए विकलांग हो जाता है, किसी की मांग का उजड़ जाता है सिन्दूर, किसी बच्चे के सिर से उसकी माता या पिता का साया उठ जाता है। किसी घर में उस घर का दीपक बुझ जाने से अंधेरा छा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इन टाले जा सकने वाले सड़क हादसों में बच्चे और किशोर अधिक मरते हैं। इनमें से कई घटनाएं स्कूल-कॉलेजों के आसपास होती है। स्कूल के पास गति 25 किमी प्रति घंटा और अस्पताल के पास 30 किमी प्रति घंटा होनी चाहिए। लेकिन अक्सर मोटर वाहन चालक यातायात नियमों की परवाह नहीं करते। यही कारण है कि भारत सड़क दुर्घटनाओं में दुनिया में अग्रणी है, जहां हर दिन 400 से ज्यादा मौतें होती हैं। वाहन चलाने में जल्दबाजी और लापरवाही इसका मुख्य कारण है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में दुनिया के केवल एक प्रतिशत वाहन हैं, लेकिन दुनिया में होने वाली कुल सड़क दुर्घटनाओं में से 6 प्रतिशत और मौतों में से 11 प्रतिशत भारत में होती हैं। पिछले दशक में सड़क दुर्घटनाओं में 13 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु और 50 लाख से अधिक घायल हुए हैं।

घटनाएं बताती हैं कि शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में सड़क दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु और विकलांगता के कई कारण हैं जैसे यातायात नियंत्रण की कमी, आवारा जानवरों को सड़क पर घूमने की आजादी, तेज़ गति, ख़राब वाहनों का मार्ग में खड़े रहना, राजमार्गों की बनावट में तकनीकी कमियाँ, सड़क संकेतों की अनदेखी, यातायात नियमों और विनियमों का पालन न करना, समय पर चिकित्सा सहायता न मिलना आदि। हैरानी की बात यह है कि 65.1 प्रतिशत लोग सड़क संकेतों के सम्बन्ध में जानते हैं लेकिन केवल 16 प्रतिशत ही इनका पालन करते हैं। दुखद तथ्य यह है कि सड़क दुर्घटना में होने वाली अधिकांश मौतों को कुछ सरल कदम उठाकर रोका जा सकता है। जैसे सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाना, सड़क पर पैदल चलने वालों का ख्याल रखना, तेज गति और ओवरटेक करने में जल्दबाजी से बचना, आवारा जानवरों को सड़क पर आने से रोकना, डिपर, इंडिकेटर लाइटों का प्रयोग और अपनी गति निर्धारित सीमा के भीतर रखना। सड़क यातायात पुलिस के गश्त और नियमों का कड़ाई से पालन करा कर भी सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है।

सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ता आंकड़ा

भारत में हर दिन 400 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें बच्चे और युवा सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। यह गंभीर समस्या समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है।

कोविड के दौरान देश में सबसे कम सड़क दुर्घटनाएं हुईं। लेकिन 2022 में एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार, दस राज्यों में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 में देश में कुल 461312 सड़क दुर्घटनाएं हुईं। इनमें 168491 लोगों की मौत हुई जबकि 443366 लोग घायल हुए। दुर्घटनाओं से प्रभावित होने वालों में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है, इनमें से अधिकांश 15 से 19 वर्ष के हैं। मरने वालों में 15 से 25 वर्ष के लोगों की संख्या अधिक ह। दुर्घटना में 20-25% को बहु-आघात और 60% को दिमाग़ी चोट लगी है। दुपहिया वाहन चालकों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना अधिक रहती है। इनमें से कुछ बदकिस्मत लोगों की जान चली जाती है तो कुछ की जिंदगी चोटों के कारण बदल जाती है। कई लोग लंबे समय तक या जीवन भर बिस्तर पर पड़े रहते हैं।

अगस्त 2020 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सड़क सुरक्षा में सुधार का प्रस्ताव रखा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य 2030 के लिए सड़क सुरक्षा एजेंडा निर्धारित किया। जिस के तहत 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करना है। संयुक्त राष्ट्र और डब्ल्यूएचओ ने अपने छत्र कार्यक्रम के तहत, सड़क सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्रवाई दशक 2021-2030 के लिए एक वैश्विक योजना विकसित की है, जिसमें सिद्ध और प्रभावी हस्तक्षेपों के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अनुशंसित उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित कार्यक्रम के अनुसार सड़क पर होने वाली मौतों को कम

करने के वैश्विक प्रयास में 2030 तक सड़क पर होने वाली मौतों की संख्या को आधा करने का संकल्प लिया है। जीवन के इस महत्वपूर्ण पहलू, सड़क दुर्घटनाओं और समाज के कमजोर वर्गों - बच्चों और युवाओं - पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यूनिसेफ ने यातायात और सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों, प्रशासकों, मीडिया और रचनात्मक पेशेवरों - रेडियो जॉकी, लेखकों और नागरिक समाज के सदस्यों को गांधीनगर, गुजरात में एकत्र किया। 15 और 16 अक्टूबर को यूनिसेफ ने गुजरात सरकार के इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस में एक राष्ट्रीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया। जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा की समस्या का व्यवहार्य समाधान खोजना था।

क्योंकि सड़क हादसों में बच्चों की मौत के आंकड़े चौंकाने वाले है। दुनिया भर हर दिन 3,200 से अधिक सड़क यातायात दुर्घटनाओं में हर मिनट 2 मौतें होती हैं, जो 5 से 29 वर्ष की आयु के बच्चों और युवाओं की मौत का प्रमुख कारण हैं।

कार्यशाला में, डॉ. जी. गुरुनाथ, एफएएमएस, सड़क सुरक्षा सलाहकार और पूर्व निदेशक, एनआईएमएचएएमएस, बैंगलोर ने सड़क सुरक्षा के पीछे के बुनियादी विज्ञान को रेखांकित किया। करीब आधे घंटे की बातचीत में उन्होंने समस्या और उसके समाधान को बेहतरीन तरीके से पेश किय। उन्होंने आश्चर्य जताया कि विकसित पश्चिम ने सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम क्यों किया है, जबकि भारत जैसा देश ऐसा व्यवहार करता है जैसे "यह मेरी नहीं, किसी और की समस्या है" और भारतीय इसी तरह गाड़ी चलाते हैं। उन्होंने सीट बेल्ट लगाने, हेलमेट पहनने, यातायात नियमों का पालन करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, निर्धारित सीमा के भीतर गति रखने और शराब पीकर वाहन चलाने से होने वाले नुकसान पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 72 प्रतिशत दुर्घटनाएं तेज गति के कारण होती हैं, जबकि मानक हेलमेट पहनने से 70 प्रतिशत दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में तत्काल ध्यान देने की जरूरत ह।

यूनिसेफ द्वारा इस मुद्दे को उठाने का

सड़क सुरक्षा पर जागरूकता

यूनिसेफ ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के प्रभावी उपायों पर चर्चा करना है।

कारण यह है कि सड़क दुर्घटनाओं के शिकार आधे से अधिक बच्चे और किशोर होते हैं। यूनिसेफ ने अपनी 2022 की रिपोर्ट 'दक्षिण एशिया में बाल और किशोर सड़क सुरक्षा' में इस मुद्दे पर प्रकाश डाला है। इसके अनुसार, 2019 में इस क्षेत्र में हुई 12.2 मिलियन मौतों में से 9% घायल हुए और सड़क पर वाहनों की टक्कर से प्रभावित एक चौथाई बच्चे और किशोर थे, जिनमें से 171,468 की मौत चोटों के कारण हुई, इनमें से 29,859 मौतें सड़क ट्रैफिक टकराव के साथ डूबने के कारण हुई। समग्र सड़क यातायात मृत्यु दर प्रति 100,000 लोगों पर 6 थी। इन दुर्घटनाओं में 20 वर्ष से कम उम्र के लोगों में 2.5 मिलियन विकलांगता-समायोजित जीवन वर्ष (DALYs) की हानि हुई।

विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क पर होने वाली मौतें ऐसी हैं जिन्हे रोका जा सकता है। फिर भी वे हो रही हैं और इनमें 10 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी हो रही है। वह इस बात पर सहमत थे कि पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि दुर्घटनाएँ क्यों होती हैं और फिर उत्पादों (वाहन सुधार) और लोगों के व्यवहार (समस्याओं) में अधिक महत्वपूर्ण बदलाव लाए जाएँ। ताकि जमीनी समस्याओं को आसानी से निपटाया जा सके इसी प्रकार मृत्यु दर में भी वृद्धि का निदान। गति पर नियंत्रण रखकर सड़क पर होने वाली मौतों की संख्या को कम किया जा सकता है, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में मौत का प्रमुख कारण तेज़ गति है।

वास्तव में, गति प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पहलू पर, प्रवर्तन सख्त और कठोर होना चाहिए, क्योंकि गति प्रेमी लोगों की मौत का कारण बनते हैं और ऐसे सभी ड्राइवर गैर इरादतन हत्या के 'दोषी' हैं जो आम आदमी की भाषा में हत्या के समान है, उन्हें बिना मकसद के हत्यारे कहा जा सकता है। यदि वे बार-बार ओवर स्पीडिंग के दोषी पाए जाते हैं, तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और उन पर लगाम लगाई जा सकती है। यदि समाधान सरल है, तो हम एक राष्ट्र के रूप में विफल क्यों हो रहे हैं? कम से कम 15 अलग-अलग विभाग ऐसे हैं जो सड़क सुरक्षा के मुद्दों से जुड़े हैं, और हर कोई कुछ न कुछ करता है, और कभी-कभी उदासीन रहता है, और समस्या हल होने के बजाय और बड़ी हो जाती है, यहाँ तक कि एक बड़ी दुर्घटना भी हो जाती है। हमें इस स्थिति को बदलना होगा। 24 घंटे जनता, सरकार, यातायात प्रशासन, विशेषज्ञ और मीडिया को मिलकर निरंतर जागरूकता अभियान चलाना होगा। जनता तक संदेश पहुंचाने से दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में कमी आएगी।

****

लेखक : पत्रकार एवं स्तंभकार तथा यू एन एन के संपादक है।

स्मारक व्याख्यान

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पर स्मारक व्याख्यान

अक्टूबर 19 को एमबीकेएम फाउंडेशन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पर मनमोहन स्वरूप माथुर स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया। इस स्मारक व्याख्यान का उद्देश्य लोगों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के महत्व को समझने में मदद करना और समाज पर इसके प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करना था।

कार्यक्रम की शुरुआत श्री मनमोहन स्वरूप जी को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई, जहां उपस्थित सभी लोगों ने उनकी स्मृति को सम्मानित किया।

एमबीकेएम फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो. प्रदीप माथुर ने स्वागत भाषण दिया। इसके बाद फाउंडेशन के महासचिव श्री राजीव माथुर ने एमबीकेएम फाउंडेशन का परिचय दिया तथा इसके उद्देश्यों और वर्तमान गतिविधियों के बारे में बताया, कि उनके बाद श्री आर.एस.अत्रोली ने श्री मनमोहन स्वरूप की स्मृतियों को याद करते हुए कहा कि, रूप जी ने अपने जीवन में सदैव समाज कल्याण को प्राथमिकता दी, तथा उनका जीवन हमारे लिए आदर्श बना रहेगा।"

श्री अनिल जोहरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञ प्रो. जीवीएस राव का परिचय कराया जिन्होंने

मेमोरियल व्याख्यान दिया। प्रो. राव का स्वागत करते हुए श्री जोहरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की।

प्रो. जीवीएस राव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उभरती हुई तकनीक के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझाया। प्रोफ़ेसर राव ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा

और व्यवसाय स्वचालन जैसे क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के व्यावहारिक उपयोगों के उदाहरण दिए। उन्होंने कहा, "कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक आधुनिक तकनीक है जिसमें हर क्षेत्र में सुधार की क्षमता है। हमें इस तकनीक का सही उपयोग करके व्यक्ति और समाज का विकास करना चाहिए।"

मनमोहन स्वरुप जी : एक अनूठा व्यक्तित्व

आर. एस.अत्रोले

श्री मनमोहन स्वरूप माथुर का जन्म 16 अक्टूबर 1933 को राजस्थान के अलवर में धनतेरस के शुभ दिन हुआ था। वे डॉ. गोविंद स्वरूप माथुर और भगवती देवी माथुर की सबसे बड़ी संतान थे। वे एक होनहार छात्र थे, उन्होंने विज्ञान और गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उच्च शिक्षा प्राप्त की।

उन्होंने 1949 में राजपुताना बोर्ड से विज्ञान स्ट्रीम में प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। शुरुआत में उन्होंने महाराजा कॉलेज, जयपुर में अध्ययन किया, बाद में उन्होंने बिरला इंजीनियरिंग कॉलेज, आनंद, गुजरात में सिविल इंजीनियरिंग कार्यक्रम में प्रवेश लिया और 1953 में 20 वर्ष की आयु में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। श्री रविशंकर प्रसाद ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजस्थान के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में सहायक अभियंता के रूप में अपना करियर शुरू किया।

38 वर्षों से अधिक समय तक उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया, अंततः मुख्य अभियंता बने और बाद में राजस्थान सरकार, पीडब्ल्यूडी के सचिव बने। माथुर ने भारत-चीन युद्ध और भारत-पाक संघर्ष के दौरान राजमार्गों, पुलों और रणनीतिक सड़कों सहित राजस्थान के बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने राजस्थान विधानसभा भवन और जयपुर-दिल्ली तथा जयपुर-मुंबई राजमार्ग जैसी परियोजनाओं में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

अपनी व्यावसायिक उपलब्धियों से परे, उन्होंने भारतीय सड़क कांग्रेस और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सहित नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभाईं। उन्होंने सक्रिय रूप से भाग भी लिया सामुदायिक सेवा, जयपुर में माथुर सभा के अध्यक्ष के रूप में सेवारत। संगीत और यात्रा के शौकीन श्री माथुर अपनी उदार भावना के लिए जाने जाते थे। 12 मार्च 2001 को उनका निधन हो गया, वे इंजीनियरिंग, सामाजिक उत्थान और समुदाय के प्रति समर्पण की विरासत छोड़ गए। सेवा। यह व्याख्यान राजस्थान के बुनियादी ढांचे की प्रगति में उनके योगदान और भविष्य की पीढ़ियों पर उनके प्रभाव का सम्मान करता है।"

सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ श्री अभिनव श्रीवास्तव ने भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अनंत संभावनाओं पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ. योगेंद्र नारायण ने अध्यक्षीय भाषण दिया। राज्यसभा के पूर्व महासचिव और भारत के पूर्व रक्षा सचिव डॉ. नारायण ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य और इसके प्रभाव पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से दुनिया में नए अवसर पैदा हो रहे हैं, लेकिन हमें इसके दुरुपयोग के प्रति भी सतर्क रहना होगा। हमें इस उभरती हुई तकनीक के सभी प्रभावों को समझना होगा।"

डॉ. नारायण ने श्री मनमोहन स्वरूप के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, "श्री स्वरूप के विचार हमेशा हमारे लिए मार्गदर्शक रहेंगे, और उम्मीद जताई कि एमबीकेएम फाउंडेशन उनके आदर्शों को आगे बढ़ाता रहेगा।"

इस अवसर पर शिक्षा, पत्रकारिता, कानून, बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र, सेना एवं स्वास्थ्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों से आये वरिष्ठ अतिथियों को भी सम्मानित किया गया। इनमें प्रो बलदेव राज गुप्ता, कर्नल अरविंद माथुर, डॉ. (श्रीमती) अर्चना वर्मा, श्री राहुल वाजपेई, प्रो लल्लन प्रसाद, डॉ. सतीश मिश्रा और श्री अरुण माथुर शामिल हैं।

कार्यक्रम के अंत में श्री नितिन अत्रोले ने धन्यवाद ज्ञापन किया तथा इस विशेष अवसर पर उपस्थित सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

स्वैच्छिक सामाजिक सेवा के लिए समर्पित गैर-लाभकारी संगठन एमबीकेएम फाउंडेशन ने इस मेमोरियल लेक्चर के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके सामाजिक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है।

इस कार्यक्रम ने उन लोगों को एक प्रेरक संदेश दिया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं। उम्मीद है कि एमबीकेएम फाउंडेशन के ऐसे प्रयास हमारे समाज को प्रगतिशील सोच और विकास के पथ पर आगे बढ़ने में मदद करेंगे।

****

समाजसेवा को समर्पित एक संगठन

राजीव माथुर

यह समारोह आयोजित करने वाले मुंशी बृजराज कुमार माथुर फाउंडेशन के बारे में कुछ शब्द कहना मेरे लिए गौरव की बात है। इस फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2022 में हुई थी और अब यह अपने दूसरे वर्ष में है। यह एक युवा और उभरता हुआ संगठन है।

संस्था और भारत सरकार द्वारा हमारे समाज के विकास और उत्थान के लिए समर्पित एक गैर-लाभकारी सामाजिक सेवा संगठन के रूप में पंजीकृत किया गया है। इस सामाजिक सेवा संगठन की स्थापना कुछ व्यक्तियों के समूह द्वारा की गई है, जिनमें वरिष्ठ नौकरशाह भी शामिल हैं , टेक्नोक्रेट, पेशेवर और अन्य, ऐसे लोग जो समाज के उत्थान और विकास के लिए समर्पित हैं।

इसका उद्देश्य समाज को वापस भुगतान करना है, जिसने उन्हें उनके सामाजिक, व्यावसायिक और आर्थिक स्तर के माध्यम से बहुत कुछ दिया है। जीवन भर। वर्तमान में, फाउंडेशन ने तीन परियोजनाओं की पहचान की है और उन पर काम कर रहा है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जनसंचार पर केंद्रित हैं।

फाउंडेशन भाग्यशाली है कि इन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बुनियादी ढांचा और आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध है जो वर्तमान में चल रही हैं। प्रगति के विभिन्न चरण. शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में, शुरुआत में, सिम्स नामक संस्था के माध्यम से लघु अवधि पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसी प्रकार मीडिया और संचार में कैरियर विकसित करने पर केंद्रित व्यक्तियों को अवसर प्रदान करने के लिए मीडिया मैप की स्थापना की गई है, यह आधारित है दिल्ली-एनसीआर और फिर उत्तराखंड की पहाड़ियों में गहना स्थित फाउंडेशन के केंद्र में एक वेदांत हम वेलनेस सेंटर फॉर हेल्थ की स्थापना की जा रही है।

हमारा भविष्य का प्रयास गहना में एक अच्छी तरह से सुसज्जित वेलनेस सेंटर बनाना है जो स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सके। स्थानीय लोगों और अन्य लोगों के लिए एक तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र जो कंप्यूटर सहित विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्रदान करेगा और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक बुनाई और सिलाई केंद्र। इन सभी गतिविधियों की योजना वर्तमान में चल रही है।

जैसा कि मैंने पहले कहा, चूंकि फाउंडेशन एक नहीं है -लाभकारी संगठन, यह स्वैच्छिक सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित है, जिसका उद्देश्य उस समाज को वापस भुगतान करना है जिसने हमें पेशेवर पहचान, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और सम्मान के माध्यम से इतना कुछ दिया है। हम उन सभी का स्वागत करते हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं उपरोक्त प्रयासों के लिए अपनी सेवाएं स्वेच्छा से प्रदान करें, ताकि उन्हें वास्तव में सार्थक और प्रभावी बनाया जा सके। हम फाउंडेशन द्वारा निकट भविष्य में प्रस्तावित गतिविधियों और परियोजनाओं में आपके सहयोग की आशा करते हैं।

जैव विविधता को हानि: भारत सबसे खराब पांच देशों में शामिल

डॉ. सतीश मिश्रा

प्रकृति संरक्षण सूचकांक (एनसीआई) 2024 के नवीनतम निष्कर्षों से पता चलता है कि भारत जैव विविधता हानि और संरक्षण प्रयासों की कमी वाले सबसे खराब पांच देशों में से एक है।

भारत का स्कोर 45.5 है और अध्ययन किए गए 180 देशों में से यह 176वें स्थान पर है। केवल किरिबाती, तुर्की, इराक और माइक्रोनेशिया का स्कोर भारत से कम है।

अक्टूबर में शुरू की गई पहली एनसीआई चार मानदंडों - भूमि प्रबंधन, जैव विविधता के लिए खतरे, क्षमता और प्रशासन, तथा भविष्य के रुझान - का उपयोग करके संरक्षण प्रयासों का मूल्यांकन करती है।

हालांकि विश्व रिपोर्ट चिंताजनक है, लेकिन मोदी सरकार की प्रतिक्रिया पूर्वानुमानित होने वाली है। यह रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज करने वाली होगी, जिसमें टिप्पणी की जाएगी कि रिपोर्ट भारत के प्रति पक्षपातपूर्ण है, आदि।

इजरायल के बेन-गुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ द नेगेव के गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज और गैर-लाभकारी वेबसाइट

> **भारत में जैव विविधता पर संकट: एनसीआई रिपोर्ट में भारत की गिरती रैंकिंग**
> "प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 की रिपोर्ट ने भारत की जैव विविधता संरक्षण में कमजोर स्थिति को उजागर किया है, जिसमें भारत 180 देशों में 176वें स्थान पर है। रिपोर्ट ने जैव विविधता की घटती आबादी और प्रदूषण जैसी गंभीर चुनौतियों पर चेतावनी दी है।"

बायोडीबी द्वारा विकसित सूचकांक के अनुसार, जैव विविधता के संरक्षण और सुरक्षा के मामले में शीर्ष पांच देश लक्जमबर्ग, एस्टोनिया, डेनमार्क, फिनलैंड और यूनाइटेड किंगडम हैं। बायोडीबी वेबसाइट पर एनसीआई 2024 प्रशस्ति पत्र में कहा गया है, "भारत दुनिया के मेगा-विविध देशों में से एक है, जिसमें दुनिया की लगभग 7-8 प्रतिशत प्रलेखित प्रजातियां कुल भूमि क्षेत्र के केवल 2.4 प्रतिशत हिस्से में फैली हुई हैं।"

"हाल ही में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने के बावजूद, भारत में वन्यजीवों और आवासों की विविधता बरकरार है। बर्फीले हिमालय से लेकर उष्णकटिबंधीय पश्चिमी घाट और शुष्क थार रेगिस्तान तक, भारत विविध जीवों को सहारा देने वाले आवासों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

"एशियाई हाथी, भारतीय गैंडे और बंगाल टाइगर जैसे प्रसिद्ध जानवरों के साथ-साथ यह पक्षियों, सरीसृपों और समुद्री जीवन की एक विस्तृत श्रृंखला का घर है। भारत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 36 वैश्विक रूप से नामित जैव विविधता हॉटस्पॉट में से चार हिमालय, इंडो-बर्मा, पश्चिमी घाट और सुंदरलैंड हैं। इसके अतिरिक्त, भारत में 10 जैवभौगोलिक क्षेत्रों में 92,037 से अधिक पशु प्रजातियाँ (जिनमें से 61,375 कीट हैं) और 45,500 पौधों की प्रजातियाँ हैं," इसमें आगे कहा गया है।

एनसीआई की वेबसाइट के अनुसार, रिपोर्ट में 180 देशों की जैव विविधता का विश्लेषण करने के लिए 25 संकेतकों की जांच की गई है। इस जैव विविधता और संरक्षण अध्ययन के प्राथमिक स्तंभ भूमि प्रबंधन, विविधता के लिए खतरे, क्षमता और शासन, और भविष्य के रुझान हैं।

एनसीआई के अनुसार, सबसे खराब रैंकिंग का मतलब है कि भारत आवास की कमी और प्रदूषण से ग्रस्त है, और वन्यजीव और पौधों की आबादी अभूतपूर्व गति से घट रही है। और संरक्षण कानून भी उम्मीद के मुताबिक नहीं है।

भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश (173), पाकिस्तान (151), श्रीलंका (90), नेपाल (60), भूटान (15) और चीन (164) सभी भारत से बेहतर रैंक पर हैं।

यहां तक कि तुलनात्मक अर्थव्यवस्थाओं में भी, मेक्सिको (42), थाईलैंड (80), इंडोनेशिया (122) और संयुक्त अरब अमीरात (111) भारत से बेहतर रैंक पर हैं।

यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। भारत में एशियाई हाथियों की संख्या 50,000 से भी कम है, जो पिछले 75 वर्षों में 50 प्रतिशत कम है। घड़ियालों की संख्या सिर्फ़ 650 है, जो एक सदी से भी कम समय में 98 प्रतिशत कम है। और बाघों की संख्या 3,890 है, जो एक सदी से भी कम समय में 96 प्रतिशत कम है।

'भविष्य के रुझान स्तंभ' के अंतर्गत सूचकांक में कहा गया है कि आने वाले वर्षों में भारत के सामने आशाजनक अवसर और जैव विविधता की गंभीर चुनौतियाँ दोनों हैं। दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देशों में से एक और 1970 के दशक के उत्तरार्ध से दोगुनी हो चुकी आबादी के साथ, देश की पारिस्थितिक संपदा लगातार खतरे में है, ऐसा उसने चेतावनी दी।

भारत की जैव विविधता को बचाने की आवश्यकता "एशियाई हाथी, घड़ियाल और बाघों की तेजी से घटती संख्या के साथ, एनसीआई रिपोर्ट भारत में संरक्षण उपायों की कमी को रेखांकित करती है। प्रभावी संरक्षण रणनीतियों और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति से ही देश की जैव विविधता को संरक्षित किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा अवैध वन्यजीव व्यापारी है, जिसकी वार्षिक बिक्री लगभग 15 बिलियन पाउंड की है, और इसलिए सूचकांक में मजबूत प्रवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया गया है।

कांग्रेस ने रिपोर्ट में भारत की निम्न रैंकिंग को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की।

"जब भी भारत किसी वैश्विक सूचकांक पर बहुत नीचे आता है, तो गैर-जैविक पीएम के ढोल पीटने वाले और जयकारे लगाने वाले लोग सूचकांक पर ही हमला कर देते हैं और कहते हैं कि यह एजेंडा-चालित व्यस्त एनजीओ द्वारा भारत को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन हाल ही में जारी प्रकृति संरक्षण सूचकांक पर क्या प्रतिक्रिया होगी, जिसमें भारत 180 देशों में से 176वें स्थान पर है।" कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया।

संरक्षण रणनीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक है, जिसमें सतत विकास का समर्थन करने वाले कानून पारित करना और पर्यावरणीय पहलों के लिए वित्त पोषण सुनिश्चित करना शामिल है।

एनसीआई सूचकांक ने आशावादी ढंग से कहा कि इस प्रतिबद्धता के साथ, भारत आगामी संरक्षण चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकता है तथा अधिक टिकाऊ और पारिस्थितिकी अनुकूल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

****

भारत की आर्थिक समृद्धि के दावे कितने सही, कितने खोखले

प्रो शिवाजी सरकार

भारत में अत्यधिक गरीबी की चुनौती बनी हुई है, 2024 में 129 मिलियन नागरिक या 13 करोड़ लोग गंभीर अभाव की स्थिति में रह रहे हैं। विश्व बैंक के अनुसार, ये व्यक्ति प्रतिदिन 180 रुपये (लगभग $2.5) या 5400 रुपये प्रति माह से कम पर गुजारा करते हैं। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट, *गरीबी, समृद्धि और ग्रह*, इस बात पर प्रकाश डालती है कि गरीबी उन्मूलन की वर्तमान धीमी गति से, वैश्विक स्तर पर निम्न-मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के बीच गरीबी को मिटाने में एक सदी से अधिक समय लग सकता है, जिन्हें प्रतिदिन $6.85 से कम पर जीवन यापन करने वाले के रूप में परिभाषित किया गया है। रिपोर्ट इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए वैश्विक नीति परिवर्तनों की आवश्यकता पर भी संकेत देती है।

कुछ प्रगति के बावजूद, भारत में गरीबी एक महत्वपूर्ण चिंता बनी हुई है। 17 जुलाई, 2023 को नीति आयोग ने रिपोर्ट दी कि देश में गरीब लोगों का अनुपात 2015-2016 के दौरान 24.8% से घटकर 2019-2021 में 14.9% हो गया है। हालाँकि, कोविड-19 महामारी ने इस प्रगति को कुछ हद तक उलट दिया, जिससे अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। आज, भारत का निम्न-मध्यम वर्ग कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें बढ़ती जीवन लागत, नौकरी की अस्थिरता, आय असमानता, उच्च कराधान और मुद्रास्फीति का दबाव शामिल है।

गरीबी की चुनौती: भारत में गंभीर स्थिति

भारत में 2024 में 129 मिलियन लोग गंभीर अभाव का सामना कर रहे हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, ये लोग प्रतिदिन 180 रुपये से कम में जीवन यापन कर रहे हैं। हाल के आंकड़े बताते हैं कि कोविड-19 ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण बाधाएं उत्पन्न की हैं, जिससे अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं।

इन परिवारों को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है मुद्रास्फीति, विशेष रूप से आवश्यक खाद्य उत्पादों की बढ़ती कीमतें। 2015 और 2022 के बीच, खाद्य पदार्थों की कीमतों में 50% की वृद्धि हुई, जिससे प्रतिदिन 6.85 डॉलर से कम कमाने वाले परिवारों पर भारी दबाव पड़ा। जबकि जीवन यापन की लागत आसमान छू रही है, वास्तविक मजदूरी वृद्धि अपर्याप्त रही है, जो 2015 से केवल 22% बढ़ी है। इस असमानता ने ग्रामीण क्षेत्रों को असमान रूप से प्रभावित किया है, जहां भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है।

2023 के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत को 125 देशों में 111वें स्थान पर रखा गया है, जो "गंभीर" भूख के स्तर को दर्शाता है। यह पिछले वर्ष के 107वें स्थान से नीचे है। ऐसी रैंकिंग चल रहे खाद्य सुरक्षा संकट को उजागर करती है जो लाखों भारतीयों, विशेष रूप से गरीबी में रहने वालों को प्रभावित करता है।

फरवरी 2024 में, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा किए गए शोध से पता चला कि भारत में गरीबी दर 2022-23 में 4.5-5% तक गिर गई, इस गिरावट का श्रेय आर्थिक पिरामिड के निचले हिस्से पर लक्षित सरकारी पहलों को दिया गया। सबसे गरीब नागरिकों के लिए जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए बनाए गए इन कार्यक्रमों ने कुछ प्रगति की है, लेकिन मुद्रास्फीति एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है।

विश्व बैंक के अनुसार, खाद्य कीमतों में हर एक प्रतिशत की वृद्धि के लिए, वैश्विक स्तर पर अतिरिक्त 10 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। भारत में, दशकीय मुद्रास्फीति औसतन 55% रही है, जिससे बुनियादी जरूरतों

को पूरा करने के लिए पहले से ही संघर्ष कर रहे लोगों की स्थिति और खराब हो गई है।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2005-2006 और 2019-2021 के बीच 415 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। हालाँकि, कोविड-19 मंदी के प्रभाव को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार, महामारी के कारण हुई आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप अनुमानित 75 मिलियन भारतीय गरीबी में गिर गए। विश्व बैंक ने यह भी अनुमान लगाया है कि 2020 में वैश्विक स्तर पर 71 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में चले गए, जिनमें से एक तिहाई भारत से थे।

इन चिंताजनक आंकड़ों के बावजूद, भारत में गरीबी का अभी भी कोई निश्चित माप नहीं है, क्योंकि 2011-12 के बाद से आधिकारिक गरीबी अनुमान प्रकाशित नहीं किए गए हैं। जबकि कुछ शोधकर्ताओं का तर्क है कि हाल के वर्षों में गरीबी के स्तर में वृद्धि हुई है, अन्य सुझाव देते हैं कि महामारी के दौरान अत्यधिक गरीबी दर में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। 2014 में, भारत ने ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1,407 रुपये प्रति माह की गरीबी रेखा प्रस्तावित की थी। आज, ये सीमाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में 1,059.42 रुपये प्रति माह और शहरों में 1,286 रुपये प्रति माह हैं, जो गरीबी को परिभाषित करने और संबोधित करने की बढ़ती चुनौती को दर्शाती हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव ने टिप्पणी की है कि भले ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन यह कई मामलों में एक गरीब देश बना हुआ है। 2,600 डॉलर की प्रति व्यक्ति आय के साथ, भारत वैश्विक स्तर पर 139वें स्थान पर है। सुब्बाराव ने बताया कि देश की आर्थिक वृद्धि के बावजूद, धन असमानता एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है, और गरीबी अभी भी व्याप्त है।

विश्व बैंक के भारत विकास अद्यतन में कहा गया है कि हाल के वर्षों में देश की आर्थिक वृद्धि सार्वजनिक अवसंरचना निवेश और रियल एस्टेट में घरेलू निवेश में वृद्धि से प्रेरित है। हालाँकि, इस वृद्धि से गरीबी उन्मूलन में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। अमीर और गरीब के बीच धन की असमानता बढ़ती जा रही है, भारत की आबादी के शीर्ष 1% - लगभग 9.2 मिलियन लोग - औसतन 53 लाख रुपये प्रति वर्ष कमाते हैं और उनके पास औसतन 5.4 करोड़ रुपये की संपत्ति है।

मुद्रास्फीति और बढ़ती लागत का प्रभाव

भारत में जीवन यापन की लागत लगातार बढ़ रही है, खासकर खाद्य वस्तुओं की। 2015 से 2022 के बीच खाद्य कीमतों में 50% की वृद्धि हुई है। यह स्थिति निम्न-मध्यम वर्ग के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, जिसके कारण लाखों परिवार दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में संघर्ष कर रहे हैं।

हडर्सफील्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कलीम सिद्दीकी ने गरीबी और असमानता को ठीक से संबोधित किए बिना आर्थिक विकास पर भारत के ध्यान की आलोचना की है। उनका तर्क है कि पिछले दो दशकों में भारत की प्रभावशाली जीडीपी वृद्धि के बावजूद, समग्र रोजगार में तेजी नहीं आई है। तेजी से विस्तार करने वाला सेवा क्षेत्र, जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान करते हुए भी, आबादी के एक छोटे हिस्से को रोजगार देता है। सिद्दीकी का मानना है कि नवउदारवादी, कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों ने गरीबी और असमानता को बढ़ा दिया है, जिससे लाखों लोग घटिया जीवन स्थितियों में रह रहे हैं।

भारत विकास की ओर अग्रसर है, इसलिए उसे यह सुनिश्चित करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कि यह विकास उसके सबसे गरीब नागरिकों के लिए सार्थक सुधार में तब्दील हो। विश्व बैंक अब स्वीकार करता है कि केवल उच्च विकास से गरीबी नहीं मिटेगी। इसके बजाय, भारत सहित वैश्विक समुदाय को काम करने की स्थितियों में सुधार, कीमतों को नियंत्रित करने और समावेशी प्रगति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बढ़ती मुद्रास्फीति, आर्थिक असमानता और महामारी के लंबे समय तक चलने वाले प्रभावों के साथ, यह सुनिश्चित करने के लिए नीति में बदलाव आवश्यक हो सकता है कि विकास से सभी नागरिकों को लाभ मिले, न कि केवल सबसे अमीर लोगों को।

आने वाले वर्षों में, भारत और दुनिया इन मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से आर्थिक नीति में बदलाव देख सकते हैं। जबकि विकास महत्वपूर्ण बना हुआ है, ध्यान एक अधिक समावेशी और समतापूर्ण समाज बनाने की ओर स्थानांतरित होना चाहिए जहां सभी नागरिकों को फलने-फूलने का अवसर मिले।***************

ब्रिक्स सम्मेलन : भारत-चीन मित्रता का सन्देश सबसे बड़ी उपलब्धि

गोपाल मिश्रा

पिछले दिनों रूस के कजान प्रांत में ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक समाप्त हुआ । जैसा हम जानते हैं ब्रिक्स उन।पांच बड़े देशों का संगठन है जिन्होंने अमेरिका के डॉलर राज्य को चुनौती देने का बीड़ा उठाया हुआ है। ब्रिक्स में बड़े सकारात्मक मामलों पर डिस्कॅशन हुआ और कई।आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रह लिए गए। हाँ, यह जरूर है कि सम्मेलन इस बात पर तैयार नहीं हुआ कि चीन की मुद्रा को ब्रिस की मुद्रा बनाया जाए और इस मामले को अभी थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन यह सम्मेलन जो है।इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के सर्वोच्च लीडर दिंगपांग की आपस में मुलाकात हुई और ये मुलाकात भी पांच वर्षों के बाद होने वाली पहली मुलाकात थी। यह सब जानते हैं इस मुलाकात से पहले भारत व चीन के सेना कमांडो ने।ये तय किया था कि अब सीमा पर कोई झगड़ा नहीं होगा और तनाव सीमा का खत्म समाप्त कर दिया जाएगा और उस एरिया को उस क्षेत्र में जो एक शांति बहाल होगी और वहाँ पर जो भी पेट्रोलिंग है वो दोनों की सहमत से होगी। मतलब?

ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसके ऊपर दोषीष्ट नेताओं मोदी और जिपिंग ने अपनी मोहर लगा दी। दोनों नेताओं ने यह कहा कि दो बड़े देशों को एशिया के दो बड़े देशों को ना से शांति सहरना चाहिए। उनको एक आर्थिक सहयोग भी करना चाहिए जिससे कि।उनकी उन देशों की उन क्षेत्रों की आर्थिक दशा और आर्थिक विकास तेजी से अनपरप सके और ये एक वास्तव में बहुत बड़ी बात थी। ये भी दर्शाती है मीटिंग कि पूरा पूरा विश्व का राजनैतिक संतुलन बदल रहा है और अब एशिया के देश।अमेरिका और पश्चिम यूरो की उस आर्थिक उस आर्थिक शिकंजे से बाहर आ रहे हैं जिसमे वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से आज तक झगड़े हुए रहे हैं। भारत और चीन का ये आपसी।और आपसी मित्रता का उदभोजन बहुत आवश्यक है और इसका एक और आपका है। पहलू यह है क्योंकि पाकिस्तान पर

> हाल ही में संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने चीनी मुद्रा युआन के लिए वैश्विक व्यापार में नई संभावनाएं खोली हैं। अमेरिका के डॉलर के स्थान पर युआन की बढ़ती स्वीकार्यता, चीन और रूस की साझा योजनाओं के साथ भारत के समावेश को भी दर्शाती है। इस सहयोग ने अमेरिका की वैश्विक स्थिति को चुनौती देने की दिशा में एक नया मोड़ लाया है।

चीन का काफी प्रभाव है। इसलिए आशा है कि भारत के संबंध न सिर्फ चीन से सुध रहेंगे, पाकिस्तान से भी सुधरेंगे जो दक्षिण एशिया के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होगा।भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध पश्चिमी देशों के आँखों में खटकते हैं, इसलिए तमाम तरीके की बातें कही जा रही है। भारतीय प्रेसवे भी इस तरह की बातें आ रही है कि क्या हम लोग चीन पर भरोसा कर सकते हैं?

क्या चीन हमारे साथ विशालघात तो नहीं करेगा?

लेकिन ऐसी कोई बात नहीं लगती है और लगता है कि यह संबंध इस क्षेत्र में शांति और आर्थिक विकास की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जिसके बारे में हर देश गंभीर है और ये इस क्षेत्र के विकास और यहाँ की आम जनता के जीवन को अच्छा बनाने के लिए।अत्यंत आवश्यक कदम है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

हाल ही में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन के साथ, वैश्विक व्यापार में विनिमय के एक वैध साधन के रूप में चीनी मुद्रा युआन को अधिक व्यापक रूप से स्वीकार किए जाने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। ब्रिक्स देशों द्वारा नई साझा मुद्रा विकसित किए जाने से पहले ही, युआन, अमेरिकी डॉलर के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उभरता हुआ दिखाई दे रहा था।

शिखर सम्मेलन के विवरण का बारीकी से अध्ययन करने पर पता चलता है कि चीन और रूस के इस साझा उपक्रम में भारत को भी शामिल होने के लिए राजी किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से अमेरिका की वैश्विक छवि को कमजोर करता है। अमेरिका विरोधी इस कार्यक्रम में भारत को लुभाने के लिए चीन चुपचाप भारत को शांति प्रस्ताव दे रहा है, वह भी बिना किसी प्रतिबद्धता के। दुर्भाग्य से, मुख्यधारा के मीडिया के मूर्ख लोग हिंदी-चीनी भाई-भाई की बयानबाजी में लिप्त हो सकते हैं या जल्द ही इसे मोदी शासन की नई सफलता के रूप में पेश कर सकते हैं।

इस बीच, चीन ने हाल ही में डॉलर के बजाय युआन डिजिटल भुगतान करके कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया है। ब्रिक्स के विस्तार के साथ, अब चीन विश्व व्यापार में अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए तैयार दिख रहा है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय, खास तौर पर अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिमी देश, चुपचाप चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नए कूटनीतिक हमले पर नज़र रखे हुए है। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाकर ही अपने एजेंडे के लिए भारतीय समर्थन हासिल कर लिया है।

इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय मीडिया की कवरेज पर्याप्त नहीं कही जा सकती, विशेषकर तब जब दोनों नेता 23 अक्टूबर को रूस के शहर कज़ान में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे।

इस समूह में ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात ने 2024 के शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के रूप में पहली बार भाग लिया। सऊदी अरब को अभी आधिकारिक रूप से शामिल होना बाकी है, लेकिन वह आमंत्रित अतिथि के रूप में संगठन की गतिविधियों में भाग लेता है। इस समूह में 1 जनवरी 2024 से नए सदस्यों को नामांकित किया गया है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।

पंक्तियों के बीच पढ़ना

पूर्वी लद्दाख में भारत-तिब्बत सीमा पर तनाव कम करके शांति और सहयोग का प्रतीक होने के बावजूद, इस बैठक के परिणाम चीनी और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अभूतपूर्व अवसर खोल सकते हैं, लेकिन अगर भारतीय मोदी को एक मर्दाना रूप देने के प्रयास में इसे भारत की सफल कूटनीति के प्रतीक के रूप में झूठी कहानियों में लिप्त रहना जारी रखते हैं, तो इसका प्रभाव देश के लिए विनाशकारी हो सकता है।

शी जिनपिंग ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल से कहा कि इतिहास की प्रवृत्ति और द्विपक्षीय संबंधों की सही दिशा को बनाए रखना हमारे दोनों देशों और दोनों देशों के लोगों के मौलिक हित में है। दोनों पक्षों को संचार और सहयोग को मजबूत करना चाहिए, रणनीतिक आपसी विश्वास को बढ़ाना चाहिए और एक-दूसरे की विकास आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। दोनों देशों को अपनी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए, विकासशील देशों की ताकत और एकता को बढ़ाने में एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक बहुध्रुवीय दुनिया और अधिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने में योगदान देना चाहिए।

नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया को इन नाजुक वार्ताओं के लिए सतर्क और उपयुक्त भी कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि "यह बैठक रचनात्मक है और इसका बहुत महत्व है। वे चीन-भारत संबंधों को रणनीतिक ऊंचाई और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से देखने और संभालने, विशिष्ट असहमतियों को समग्र संबंधों को प्रभावित करने से रोकने और क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और समृद्धि को बनाए रखने और दुनिया में बहुध्रुवीयता को आगे बढ़ाने में योगदान देने पर सहमत हुए।"

भारत और चीन के नेताओं के बीच हुई वार्ता के दौरान शांति और सहयोग की बात की गई, लेकिन इसे मोदी सरकार की कूटनीतिक सफलता के रूप में देखने में सतर्कता बरतनी चाहिए। दोनों देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता बनी रहे।

यह स्वाभाविक है कि सरकार के शीर्ष स्तर पर होने वाले ऐसे संवादों के दौरान विस्तृत जानकारी न दी जाए। मोदी और जिनपिंग से परिणामों के बारे में विस्तृत जानकारी देने की अपेक्षा नहीं की गई थी, लेकिन अब मीडिया और उद्योगों को फिर से खुलने वाले अवसरों का आकलन करना होगा। दिलचस्प बात यह है कि दो घटनाएं एक साथ हुईं, पहली यह कि भारत में चल रहे त्योहारी सीजन के दौरान 84,000 करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजी का पलायन हुआ। इस दौरान चीन ने कैंटन फेयर में अपने औद्योगिक उत्पादों का प्रदर्शन भी किया।

इस चल रही प्रदर्शनी को ऑनलाइन देखने से भी पता चलेगा कि आर्थिक विकास में थोड़ी सी बाधा के बावजूद चीनी उत्पाद महाद्वीपों में बेजोड़ बने हुए हैं।

मिथक और वास्तविकता

एक दशक पहले अपने उद्घाटन के बाद से ही मोदी सरकार अनावश्यक बयानबाजी में लगी हुई है और मीडिया, जिसमें टेलीविजन चैनल और अखबार शामिल हैं, मोदी समर्थक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ, सरकार के झूठे प्रचार को ही दोहरा रहे हैं। उदाहरण के लिए, 'मेक इन इंडिया' अभियान ऐसी ही बयानबाजी का एक हिस्सा है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत में कई तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इसे आउटसोर्स किया गया है। सरकारी दावों के बावजूद, भारतीय विनिर्माण क्षेत्र सरकार की उदासीनता के कारण लगातार प्रभावित हो रहा है, तथा भाजपा शासित राज्यों में भी सक्रिय राजनीतिक माफियाओं के साथ-साथ अत्यधिक कर प्रणाली के कारण भी यह प्रभावित हो रहा है।

भारत में इंजीनियरिंग स्नातकों की बड़ी संख्या होने के बावजूद, वित्तीय संस्थाएं शायद ही कभी उद्यमियों को समर्थन देती हैं, सिवाय सरकार समर्थक मीडिया चैनलों में कुछ दावों के।

चीनी कंपनियों पर लगाम

भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हालिया बयान में कहा गया है कि भारत में चीनी कंपनियों पर मौजूदा प्रतिबंध जारी रहेंगे। हालाँकि, मोदी-शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद स्थिति काफी अलग है। चीनी कंपनियां जल्द ही विश्व बाजारों में निर्यात के लिए औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर सकती हैं। उन्हें कर लाभ भी मिलेगा। इसलिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चीनी निवेश के खिलाफ भारतीय वित्त मंत्री का साहसिक बयान जल्द ही भुला दिया जाएगा।

****

राजनीति समीकरणो को बदलते पंजाब के उपचुनाव

प्रभजोत सिंह

एक ऐसे राज्य में, जहाँ सत्ताधारी दल के पास मजबूत बहुमत हो, वहाँ उपचुनावों का महत्व अक्सर कम हो जाता है। फिर भी, पंजाब में चार विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव महत्वपूर्ण हैं। इन उपचुनावों से आम आदमी पार्टी की स्थिति पर शायद कोई खास असर न पड़े, लेकिन राज्य के बदलते राजनीतिक परिदृश्य के मद्देनज़र यह चुनाव अहम है। शिरोमणि अकाली दल, जिसने कई वर्षों तक अकाली दल के साथ गठबंधन में प्रमुख भूमिका निभाई है, इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा है, जिससे अन्य पार्टियों के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही, कांग्रेस भी अपनी पुरानी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रही है।

जब डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल, बरनाला और गिद्दड़बाहा के चार विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता 13 नवंबर को लोकसभा के लिए निर्वाचित विधायकों के स्थान पर अपने नए विधायकों को चुनने के लिए मतदान करेंगे, तो यह पंजाब के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज हो जाएगी।

सुखजिंदर सिंह रंधावा, डॉ. राज कुमार चब्बेवाल, श्री गुरमीत सिंह मीत हायर और श्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग - सभी मौजूदा विधायक जून में हुए पिछले आम चुनावों के दौरान लोकसभा के लिए चुने गए थे।

पंजाब में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव चार महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों के लिए चुनावी युद्ध की शुरुआत हैं। आम आदमी पार्टी की स्थिति पर इसका सीधा प्रभाव न पड़ने की संभावना है, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव के चलते यह चुनाव महत्वपूर्ण बन जाते हैं। शिरोमणि अकाली दल की अनुपस्थिति ने अन्य पार्टियों को आत्मविश्वास से भर दिया है, जिससे कांग्रेस और भाजपा ने अपने-अपने चुनावी रणनीतियों को और मजबूती दी है।

उनके द्वारा खाली की गई सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को होने वाले हैं।

यह दूसरी बार होगा जब देश की सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) की भागीदारी के बिना चुनावी लड़ाई लड़ी जाएगी। इससे पहले 1991 के चुनावों को अंतिम समय में रद्द किए जाने के विरोध में एसएडी ने फरवरी 1992 में आम चुनावों का बहिष्कार किया था।

इस बार उपचुनाव से दूर रहने की वजह अलग है। पांच तख्तों के जत्थेदारों द्वारा पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को 'तनखैया' घोषित करने का निर्देश पार्टी की कोर कमेटी को 13 नवंबर के चुनावी संग्राम से दूर रहने का तत्काल उकसावा दे सकता है।

यह निर्णय राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब यह मामला प्रतिष्ठित गिद्दड़बाहा सीट पर स्थानांतरित हो गया है, जो परंपरागत रूप से दल और विशेष रूप से बादल परिवार का गढ़ रहा है।

उपचुनाव की तारीखों की घोषणा से बहुत पहले ही अकाली दल समेत सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने संपर्क कार्यक्रम शुरू कर दिए थे। सुखबीर बादल इस निर्वाचन क्षेत्र में तब तक सक्रिय थे, जब तक कि उनके करीबी सहयोगी और इस सीट के लिए एक समय पसंदीदा रहे हरदीप सिंह उर्फ डिंपी ढिल्लों ने बगावत करके दल की प्राथमिक सदस्यता नहीं छोड़ दी। कुछ दिनों बाद वे राज्य की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और उसके बाद पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किए गए।

लुधियाना संसदीय सीट से मौजूदा सांसद अमरिंदर सिंह उर्फ राजा वड़िंग के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद यह सीट रिक्त हो गई थी। अब कांग्रेस ने

पंजाब के उपचुनाव 13 नवंबर को चार विधानसभा सीटों पर होंगे, जहां मतदाता नए विधायकों का चुनाव करेंगे। शिरोमणि अकाली दल के इस बार चुनाव में न भाग लेने के फैसले ने अन्य राजनीतिक दलों के लिए अवसर पैदा किया है। कांग्रेस अपनी पुरानी स्थिति को पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। यह चुनाव राज्य की राजनीतिक दिशा को तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

उनकी पत्नी अमृता वड़िंग को 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है।

देश में गठबंधन की राजनीति में कभी अग्रणी रहा पंजाब अब गठबंधनों को अलविदा कहने में आगे आ गया है। अपने पारंपरिक सहयोगी शिरोमणि अकाली दल से अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़े थे। अपनी राजनीतिक भूख को बढ़ाने के लिए अब वह सीमावर्ती राज्य के "मुक्त जल" को परखने की कोशिश कर रही है।

अगला विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने की घोषणा करके, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल दोनों से शीर्ष नेतृत्व के अप्रत्याशित आगमन से इसकी महत्वाकांक्षा को और बल मिला है।

भाजपा ने उन चार विधानसभा सीटों में से तीन के लिए भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिन पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। इनमें सबसे प्रमुख सीट गिद्दड़बाहा है, जहां उसने बादल परिवार से दूसरे सबसे योग्य उम्मीदवार मनप्रीत सिंह को मैदान में उतारा है, यह उम्मीद करते हुए कि डिंपी ढिल्लों के जाने के बाद सुखबीर बादल मैदान में कूद सकते हैं।

कोई भी पार्टी यह कल्पना नहीं कर सकती थी कि जो जत्थेदार सुखबीर बादल को 'तन्खा' (धार्मिक सजा) सुनाने का इंतजार कर रहे थे, वे अपना फैसला सुनाए जाने तक उन्हें किसी भी राजनीतिक गतिविधि से प्रतिबंधित कर देंगे, क्योंकि अकाली दल नेतृत्व द्वारा उन्हें शीघ्र फैसला सुनाने के लिए मनाने के सभी प्रयास विफल हो गए।

इन "असफल" प्रयासों के कारण सुखबीर सिंह बादल के भरोसेमंद सिपहसालार विरसा सिंह वल्टोहा को जत्थेदारों का गुस्सा झेलना पड़ा। उन्हें दल की प्राथमिक सदस्यता छोड़ने और अगले 10 सालों तक दल से दूर रहने का आदेश दिया गया।

जत्थेदारों के मूड को भांपते हुए दल की कोर कमेटी ने 13 नवंबर के उपचुनावों से दूर रहने का फैसला किया, जिससे अन्य तीन पार्टियों - आप, भाजपा और कांग्रेस के लिए मैदान खुला रह गया।

****

लेखक : वरिष्ठ पत्रकार है , खेल कूद पत्रकार्ता में उनकी विशेष रूचि है और उन्होंने साथ ओलिंपिक कवर किये है। खेल - कूद के साथ ही वे व्यापर, वित्ति , स्वास्थ्य , विमानन और सिख-पंजाब राजनीति के भी विशेषज्ञ माने जाते है।

सुविचार

****

किसी की परवाह करना आसान है, लेकिन किसी को आपकी परवाह करने पर मजबूर करना मुश्किल है, इसलिए कभी भी उस व्यक्ति को मत खोइए जो वास्तव में आपकी परवाह करता है

****

जब आप हारें तो साहसी बनें, जब आप जीतें तो शांत रहें। चेहरा बदलने से कुछ नहीं बदल सकता लेकिन बदलाव का सामना करने से सब कुछ बदल सकता है।

****

क्रोध अकेला आता है, लेकिन हमारे अंदर से सारे अच्छे गुण छीन लेता है। धैर्य भी अकेला आता है, लेकिन हमारे अंदर से सारे अच्छे गुण बाहर लाता है।

****

गलतियाँ जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता एक पूरी किताब है। इसलिए एक पन्ने के लिए पूरी किताब बंद मत करो।"

****

उमर अब्दुल्ला के लिए मुख्यमंत्री पद काँटों का एक ताज

अश्विनी कुमार

नेशनल कांफ्रेंस के उप प्रधान और फ़ारूक़ अब्दुल्ला के बेटे , उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के पहले मुख्य मंत्री तो बन गए है लेकिन उनकी उप राज्यपाल, मनोज सिन्हा के साथ प्रशासन चलने पर खटपट चलतीं रहेगी । कारण यह होगा कि इससे पहले वह पांच जनवरी २००९ में छह साल के लिए मुख्य मंत्री पहली बार बने थे और उनके पास फूल पावर थी । लेकिन इस बार उमर पांच साल के लिए मुख्य मंत्री रहेंगे। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कांफ्रेंस को काफी वोट बैंक कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू में भी मिला है । पंद्रह साल पहले बने मुख्यमंत्री और अब के मुख्यमंत्री में ज़मीन और आसमान का फर्क रहेगा . उमर अब्दुल्ला के सिर पर इस बार काँटों का ताज है. साथ में काफी चुनौतियां भी है। जिस तरह से नेशनल कांफ्रेंस पर लोगो ने विश्वास करके वोट दिया है उससे लोगों की उम्मीदें भी काफी बड़ी हुई है ।उनको हर कदम सोच समझ कर लेना होगा। चाहे उनके केंद्र के साथ अच्छे रिश्ते हो या उपराज्यपाल, मनोज सिन्हा के साथ . उमर अब्दुल्ला को यह भी याद रखना होगा कि इस बार उन्हें जम्मू से मज़बूत विपक्ष मिला है और वह भी बीजेपी की तरफ से बाकी का विपक्ष बिल्कुल साफ है जम्मू में । बीजेपी को इस बार हिन्दू वोट बैंक जिलों में पहली बार २९ सीटे मिली है। इसलिए विधान सभा के अन्दर और विधान सभा के बाहर उमर अबदुल्ला को एक मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। जोकि मुख्यमंत्री, उमर अब्दुल्ला के लिए इनको संभालना मुश्किल होगा कयोंकि नेशनल कांफ्रेंस का कांग्रेस के साथ गटबंदन है। चाहिए कांग्रेस उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में ज्वाइन नहीं किया। कांग्रेस के प्रधान , तारिक़ हामिद कररा ने कहा कि जब तक केंद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा नहीं देगी तब तक कांग्रेस मंत्री मंडल में नहीं शामिल नहीं होगी ।

उमर अब्दुल्ला का दूसरा कार्यकाल जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में कई चुनौतियों से भरा होगा। इस बार, उनके पास पहले जैसी पूरी ताकत नहीं है, और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ प्रशासनिक तालमेल बिठाना आसान नहीं होगा। साथ ही, बीजेपी द्वारा जम्मू में मजबूत विपक्ष के रूप में उभरने के कारण विधानसभा में उन्हें कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ उन्हें गठबंधन सहयोगियों से भी निपटना होगा।

अगले पांच साल उमर अब्दुल्ला के लिए काफी मुश्किल के होने वाले है क्योंकि लोगो की उम्मीदें उन पर काफी टिकी हुई है। चाहे ,वह कश्मीर की जनता हो या जम्मू के लोग। कश्मीर घाटी में नेशनल कांफ्रेंस को इस लिए खुलकर वोट मिले कयोकि पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में आर्टिकल ३७० और ३५ ए को वापिस लाना , जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने, पुराने जम्मू कश्मीर में चल रहे सालाना दरबार मूव को दोबारा शरू करना , बढ़ती हुई बेरोजगारी का मुद्दा ,कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू की जनता को भी न्याय दिलाना और कानून व्यवस्था को बहाल रखे रखना यह सारे मुद्दे उमर अब्दुल्ला को सरकार चलाने में तंग करेंगे। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से सोनमर्ग , गुलमर्ग और जम्मू के अखनूर इलाके भट्ठल में आतंकवादी हमले हुए है वह उमर अब्दुल्ला के लिए चिंता का विषय है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षाबल का कंट्रोल उप राज्यपाल, मनोज सिन्हा के पास है। 5 अगस्त 2019 से पहले यूनिफाइड कमांड की बैठक मुख्यमंत्री लेते थे लेकिन अब मनोज सिन्हा ले रहे है। इस पर मुख्यमंत्री , उमर अब्दुल्ला के पॉलिटिकल एडवाइजर, असलम वाणी के कहा है कि जम्मू कश्मीर में डुअल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलेगी। यूनिफाइड कमांड की बैठक मुख्यमंत्री, उमर अब्दुल्ला लेने चाहिए न के उप राज्यपाल, मनोज सिन्हा।

जहां तक जम्मू कश्मीर से हटाए गए आर्टिकल ३७० और ३५ ए को दुबारा वापिस लाने की बात है उमर अब्दुल्ला ने चुनावो के बाद ही साफ कर दिया था कि जिस बीजेपी सरकार ने ३७० और ३५ ए का दफ़न किया उनसे वापस लाने की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनकी पार्टी हर फोर्म पर इस मुद्दे को जिन्दा रखे गई। जब भी केंद में बीजेपी की सरकार हटेगी तब नेशनल कांफ्रेंस इस मसले को नई दिल्ली के समकक्ष रखेगी।

उमर अब्दुल्ला ने जनता से यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा वह फिर खटखाए गए और वह से न्याय मिलने की उनको पूरी उम्मीद है.

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उमर अब्दुल्ला के पास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे , जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्ज़ा दिलवाने के इलावा दरबार मूव की बहाली के साथ बेरोज़गारी का मसाला सबसे टॉप पर है। इन मामलो से निपटने के लिए उनको केंद के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने होंगे। अगर वह ऐसा करने में कामयाब हो जाते है तो केंद सरकार तभी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा दे सकती है लेकिन उनको इसके लिए कांग्रेस को ज्यादा भाव नहीं देना। हालाकिं प्रधानमंत्री , नरेंद्र मोदी और ग्रह मंत्री , अमित शाह ने चुनावी भाषणों में भी कहा है कि नई सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर को दुबारा राज्य का दर्जा दिया जायेगा। लेकिन केंद ने इसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है।

उमर अब्दुल्ला ने दरबार मूव की दुबारा बहाली की बात की है लेकिन यह सब तभी हो पायेगा जबतक कि उप राज्यपाल, मनोज सिन्हा और केंद सरकार इसको हरि झंडी नहीं देते। केंद शासित जम्मू कश्मीर के कानूनों के मुताबिक महत्वपूर्ण विषयो पर उप राज्य पाल की सहमति ज़रूरी होती है। नेशनल कांफ्रेंस को उम्मीद है कि स्टेट हुड की मांग शायद केंद पूरी कर दे लेकिन अगर इस में देरी होती है तो जम्मू कश्मीर सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले है। नेशनल कांफ्रेंस चाहती है कि बिना किसी खींच तनाव से अगर यह दोनों मुद्दों का फैसला हो जाता है तो किसी हद तक लोग खुश हो जायेगे।

जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की बहाली का मुद्दा नेशनल कांफ्रेंस के साथ साथ बीजेपी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण बन चूका है। दरबार मूव की परंपरा १८७२ से २०२१ तक चलती रही , यानिकि सरकारी दफ्तर छह महीनो के लिए सर्दियों में श्रीनगर से जम्मू में आ जाते थे और गर्मियों में वापिस कश्मीर चले जाते थे। लेकिन दरबार मूव परंपरा उप राज्यपाल , मनोज सिन्हा ने तीन साल पहले यह कह कर खत्म कर दिया था कि हर साल सामान शिफ्टिंग पर करीब १३० करोड़ का खर्चा आता है। मनोज सिन्हा का तर्क यह था की डिजिटल जम्मू कश्मीर बनने से दरबार मूव का रहना ठीक नहीं है। लेकिन राजा महाराजाओ दवारा चलाये गये दरबार मूव खत्म करने पर जम्मू की जनता बीजेपी से काफी नाराज़ है। जम्मू चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रधान , अरुण गुप्ता ने कई बार कहा है कि जब से दरबार मूव का जम्मू आना बंद हो गया है तब से जम्मू का बिज़नेस खत्म हो गया है। दरबार मूव वापिस लाने की मांग जम्मू में अंडर करंट पकड़ रही है और कभी न कभी

दरबार मूव की बहाली और जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उमर अब्दुल्ला के कार्यकाल के प्रमुख मुद्दे बन गए हैं। कश्मीर घाटी के लोगों ने उनके चुनावी घोषणापत्र का समर्थन किया, जिसमें धारा 370 और 35ए की बहाली, बेरोजगारी को कम करना, और जम्मू-कश्मीर के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। इन मुद्दों पर जनता की उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन केंद्र और उपराज्यपाल के साथ इन पर सहमति बिठाना आसान नहीं होगा।

आने वाले दिनों में बीजेपी के २९ विधयकों पर जम्मू से दबाव आएगा। गौरतलब है कि १९८७ में तत्कालीन मुख्य मंत्री , फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने भी इसी तर्क पर दरबार मूव खत्म करके कश्मीर में रखने का फैसला किया था। करीब दो महीने जम्मू में हड़ताल होने के बाद फ़ारूक़ अब्दुल्ला को वह आर्डर वापिस लेना पड़ा था। उनके बेटे , उमर अब्दुल्ला को भी आने वाले दिनों में इस तरह की सिथिति देखनी पड़ सकती है। जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के प्रधान और उमर अब्दुल्ला के पिता, डॉ फारूक अब्दुल्ला ने कहा कहा है कि स्टेट हुड मिलने के बाद उमर सरकार दरबार मूव वापिस लाएगी।

सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना ,उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के नए कानूनों और मुख्य मंत्री की पावर को लेकर आने वाली है। पहली बार जब वह २००९ से २०१५ तक मुख्यामंत्री थे तब उनको पूरे अधिकार थे लेकिन ऐसा नहीं है। अब किसी सेंट्रल सर्विस के सेक्रेटरी को ट्रांफर करने के लिए उनको उप राज्यपाल , मनोज सिन्हा की सहमति की ज़रुरत होगी।

जिस तरह से नेशनल कांफ्रेंस को लोगो का मैंडेट मिला है उससे अपेक्षाए भी और भी बढ़ गई है लेकिन उमर अब्दुल्ला के लिए सभी मांगे पूरी करना मुश्किल होगा। राजनीतिक तौर पर कश्मीर में मेहबूबा मुफ़्ती की पीडीपी और जम्मू में बीजेपी उनको आसानी से सरकार चलाने नहीं देगी। मेहबूबा मुफ़्ती ने शपथ समारोह के बाद ही मांग कर दी की नई विधानसभा को ५ अगस्त २०१९ के केंद सरकार के फैसले को गलत ठहरना चाहिए। जोकि उमर अब्दुल्ला के लिए खतरनाक होगा। हालांकि,उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को काउंटर करने के लिए बॉर्डर जिला , राजौरी के नौशेरा विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रधान ,रविंदर रैना को हराने वाले नेशनल कांफ्रेंस के नेता सुरिंदर चौधरी को उपमुख्य मंत्री बना दिया है. यानिकि उमर ने एक तीर से दो निशान मारे है। कांग्रेस को जम्मू इलाके से एक भी हिन्दू इलाके से सीट न मिलने के कारण नेशनल कांफ्रेंस के जम्मू में और दिकते बढ़ गयी है। नेशनल कांफ्रेंस के प्रधान और पूर्व मुख्य मंत्री , डॉ फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने भी माना है कि उनके बेटे , उमर अब्दुल्ला को काफी मेहनत करनी पड़ेगी।

****

लेखक : वरिष्ठ पत्रकार है

श्रीमती इंदिरा गाँधी जन्मदिवस, 19 नवंबर

इंदिरा गाँधी, निहित स्वार्थों का षड्यंत्र और आपातकाल

प्रो प्रदीप माथुर

विश्व के इतिहास में जितनी भी महिलाएं सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंची है, उनमें श्रीमती इंदिरा गाँधी का स्थान बहुत ऊंचा है। अपने राजनीतिक जीवन में अगर श्रीमती गाँधी दो गलतियाँ न करती तो शायद वो विश्व की अब तक की सबसे महान और सफल महिला शासक होती। अपने दोनों कार्यकाल में जो कि वर्ष 1966 से 1977 तक फिर वर्ष 1980 से लेकर 84 तक चले इंदिरा गाँधी ने एक एक बड़ी गलती करी। पहली गलती थी 1975 में आपातकाल लगाना और दूसरे कार्यकाल में उनकी गलती थी सिक्खो के सबसे पवित्र धर्म स्थल स्वर्ण मंदिर पर सैनिक कार्यवाही जो बाद में उनकी हत्या का कारण बनी।

आपातकाल के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। इंदिरा गाँधी को तानाशाह और लोकतंत्र विरोधी और भी जाने क्या क्या कहा गया है। आज उनकी मृत्यु के 40 साल बाद भी प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर भुनाने का प्रयास करती है। अभी पिछले दिनों जब विपक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा का शासन अधिनायकवादी है और मोदी जी तमाम ऐसे फैसले कर रहे हैं जो कि जनतांत्रिक नहीं है भाजपा सरकार ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए आपातकाल को एक नेशनल ऑब्सर्वेशन डे बना दिया। बात स्पष्ट थी कि आपातकाल के मुद्दे को जो बहुत पुराना हो चुका है उसको

दोबारा पुनः जीवित किया जाए।

आपातकाल के बारे में कई बातें कही जाती हैं। लेकिन हमें दो बातें स्पष्ट समझनी चाहिए। आपातकाल इंदिरा गाँधी ने इसलिए नहीं लगाया था कि वह अपनी कुर्सी बचाना चाहती थी या उनको किसी भी तरह से सत्ता से हटने का डर था। वह वास्तव में समझती थी कि उनकी सरकार के विरुद्ध हो रहे आन्दोलन से देश की सुरक्षा को खतरा है। सेना और पुलिस को सरकारी आदेश न माननेवाली बात कह कर सम्पूर्ण क्रांति के जननायक जय प्रकाश नारायण (जेपी) ने इंदिरा गाँधी के इस विश्वास को और भी मजबूत बनाया।

श्रीमती इंदिरा गाँधी को उनके करीबी और बहुत ही मज़े हुए और सुलझे हुए कुछ सहयोगियों ने सुझाव दिया था कि आपातकाल लगाने में कोई हर्ज नहीं है और थोड़े दिनों के बाद इसको हटाया जा सकता है।

अंदर की कहानी यह है कि जब जेपी का संपूर्ण क्रांति आंदोलन चल रहा था उस समय संजय गाँधी जो कि इंदिरा गाँधी के छोटे पुत्र होने के साथ साथ उनके निकट राजनीतिक सहयोगी भी थे, बहुत परेशान थे। उनका मानना था कि यह आंदोलन देश की उस प्रगति के रास्ते में आ रहा है जिसका वह सूत्रधार बनना चाहते थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल संजय गाँधी के बहुत करीबी थे। संजय गाँधी ने उनसे बात की और बंसीलाल ने यह बात राज्य के तत्कालीन गवर्नर बीएन चक्रवर्ती से कही। चक्रवर्ती साहब ने बताया कि संविधान में इस समस्या से निबटने का प्रावधान और आपातकाल लगाकर उसके द्वारा सम्पूर्ण क्रांति का पूरा अभियान रोका जा सकता है और विरोधी

नेताओं के मुँह बंद किए जा सकते हैं।

राज्यपाल बी एन चक्रवर्ती वरिष्ठ अधिवक्ता थे और उनको कानून की बहुत अच्छी जानकारी थी। उन्होंने आपातकाल के प्रावधान पर लिख कर नोट बनाया। प्रस्ताव लेकर संजय गाँधी इंदिरा गाँधी के पास गए। लेकिन श्रीमती इंदिरा गाँधी एकदम से राजी नहीं हुई। वो तभी भी अनिश्चय की स्थिति में थी और इसलिए राय लेने के लिए उन्होंने तत्कालीन मंत्री और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे से बात करी। सिद्धार्थ शंकर रे और श्रीमती गाँधी के बहुत पुराने संबंध थे यहां तक कि वह इंदिरा गाँधी को प्रधानमंत्री ना कहकर इंदिरा कहकर बुलाते थे। सिद्धार्थ शंकर रे कानून के विशेषज्ञ और बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे। उनका देश के बौद्धिक समाज में बहुत आदर था जब सिद्धार्थ शंकर रे ने कहा की आपातकाल लगाने में कोई हर्ज़ नहीं है तब श्रीमती गाँधी इस बात के लिए तैयार हुई और उन्होंने तत्कालीन गृहमंत्री जगजीवन राम से कहा और देश में आपातकाल लागू कर दिया गया।

लगभग 18 महीने के आपातकाल के बाद वर्ष 1977 में चुनाव हुए और उनमें नयी बनी जनता पार्टी ने श्रीमती गाँधी की कांग्रेस को सत्ता के बाहर कर दिया। श्रीमती गाँधी और संजय गाँधी दोनों चुनाव हार गए। ये सब बाते हम जानते हैं लेकिन मूल प्रश्न यह है कि क्या आपातकाल का कारण केवल कोर्ट का वह फैंसला था जिसके तहत श्रीमती इंदिरा गाँधी का लोकसभा चुनाव अवैध पाया गया था। आइये हम इंदिरा गाँधी के राजनैतिक विरोध की पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते है।

वर्ष 1966 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्रीमती गाँधी को कांग्रेस के तमाम पुराने नेताओं का विरोध सहना पड़ा। ये वो नेता थे जिन्होंने श्रीमती गाँधी को इस आशा से प्रधानमंत्री बनाया था या बनने में सहायता की थी कि वह एक कमजोर प्रधानमंत्री रहेंगी और वो जैसा चाहेंगे, करते रहेंगे और देश के शासन पर उनकी पकड़ बनी रहेगी। लेकिन उनकी आशा के विपरीत इंदिरा गाँधी एक लोकप्रिय और दमदार प्रधानमंत्री साबित हुई। उन्हें व्यापक जन समर्थन मिला और एक युवा नेता के रूप में उन्होंने नई पीढ़ी को पूरी तरह प्रभावित किया। श्रीमती गाँधी ने कई लोकलुभावन निर्णय लिए और एक बिलकुल स्वतंत्र लाइन पर चलना शुरू किया। कांग्रेस के पुराने नेता इससे खुश नहीं थे। उन्होंने श्रीमती गाँधी के खिलाफ़ एक मुहिम चालू कर दी। इसी के तहत कांग्रेस का विभाजन भी हुआ और आपसी संघर्ष का इतिहास शुरू हुआ।

जयप्रकाश नारायण और सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन

इंदिरा गाँधी के खिलाफ़ समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत की। आरएसएस के समर्थन से बढ़ते इस आंदोलन में जनता का बड़ा समर्थन जुटा, जिससे इंदिरा गाँधी की सरकार को चुनौती मिली और आपातकाल लगाने का विचार सामने आया।

कैसे डॉ जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति पद पर झगड़ा हुआ और श्री वीबी गिरी किस तरह राष्ट्रपति बने, इन सब बातो का इतिहास साक्षी है। लेकिन इसके पीछे एक और चीज़ थी जिस पर ध्यान नहीं गया। श्रीमति गाँधी ने स्पष्ट किया वह भारत की गरीब जनता के साथ है और इस दिशा में उन्होंने बैंको का सरकारीकरण तथा प्रिवी पर्स बंद करने जैसे कई आर्थिक रूप से क्रन्तिकारी कदम उठाये। इनसे देश के निहित स्वार्थ वाले उस वर्ग के हितो पर सोधा प्रहार हुआ जो की देश के व्यापार और अर्थव्यवस्था पर अपना पूरा शिकंजा कायम करते आये थे। उनको लगा कि श्रीमती गाँधी का पुरजोर राजनीतिक विरोध नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो कि अर्थतंत्र पर उनका शिकंजा और इस शिकंजे के साथ देश पर उनका वर्षों से चला आ रहा वर्चस्व ही समाप्त ना हो जाए।

जैसा हम सब जानते है वर्ष 1971 के भारत - पाक युद्ध में इंदिरा गाँधी ने पाकिस्तान को तोड़ा, बांग्लादेश को आजाद कराया और एक बड़ी ऐतिहासिक विजय हासिल करी। इसके बाद श्रीमती गाँधी का प्रभाव और लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। श्रीमती गाँधी के विरोधियो को इससे बड़ी चिंता हुई और उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू किया। वर्ष 1973 में गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ जो कि ज्यादा

सफल नहीं हुआ। इसके बाद इंदिरा गाँधी के विरोधी दलों ने जय प्रकाश नारायण को पकड़ा। जय प्रकाश नारायण नेहरू जी के बड़े करीब थे और इंदिरा गाँधी को अपनी पुत्री की तरह मानते थे, लेकिन किसी बात पर उनका और इंदिरा गाँधी के अहम का टकराव हो गया और जय प्रकाश नारायण ने इंदिरा गाँधी के विरूद्ध सम्पूर्ण क्रांति आन्दोलन शुरू किया।

जय प्रकाश नारायण समाजवादी विचारधारा से आए थे। भारत में समाजवाद की स्थापना में उनका बहुत बड़ा नाम था। जय प्रकाश नारायण को चुपचाप आरएसएस ने समर्थन देना शुरू किया। अगर आज संघ परिवार देश में सत्ता पर काबिज है तो इसकी जड़ें उसी आन्दोलन से आती हैं। उन्होंने जय प्रकाश नारायण के सम्पूर्णक्रान्ति आंदोलन में घुसपैठ करी और धीरे धीरे देश की राजनीति में अपना स्थान बनाया। जय प्रकाश नारायण से उनके कुछ लोगों ने कहा भी की इस आंदोलन में संघ परिवार के सांप्रदायिक लोग आ गए हैं, लेकिन जय प्रकाश नारायण ने इस बात की परवाह नहीं करी।

धीरे धीरे सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन बढ़ता चला गया। पर हद तब हुई की जब जय प्रकाश नारायण ने एक दिल्ली में रैली करी और यहाँ तक कहा कि देश की सेना और पुलिस को सरकार की बात नहीं माननी चाहिए क्योंकि ये सरकार भ्रष्ट है। पुलिस और सेना को सरकार का विरोध करने के लिए उकसाने वाली बात तो राष्ट्रद्रोह की बात थी और सचमुच बहुत गम्भीर बात थी। तब श्रीमती गाँधी को इस स्थिति से निबटने के लिए कुछ कुछ कदम उठाने के बारे में सोचना पड़ा और आपातकाल लगा।

ये निर्णय गलत साबित हुआ। श्रीमती गाँधी को इसका परिणाम भुगतना पड़ा और इतनी लोकप्रिय नेता होने के बाद भी वर्ष 1977 के चुनाव में उनकी और उनके पुत्र संजय गाँधी की हार हुई।

आपातकाल का विवाद और इसके परिणाम

1975 में लगाए गए आपातकाल को इंदिरा गाँधी के आलोचक उनके सबसे बड़े विवादास्पद निर्णयों में गिनते हैं। उनके सहयोगियों की सलाह पर उन्होंने यह कदम उठाया, लेकिन इसका परिणाम नकारात्मक रहा। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का उभार और इंदिरा गाँधी की हार ने इस फैसले के प्रति जनता की असहमति को उजागर किया।

आपातकाल की पृष्ठभूमि क्या थी, इसके बारे में लोग नहीं जानते। पृष्ठभूमि थी श्रीमती इंदिरा गाँधी के खिलाफ़ एक षड्यंत्र जो की देश की व्यापारिक, आर्थिक निहित स्वार्थ और साम्प्रदायिक शक्तियों की सयुक्त परियोजना थी। इसमें उन्होंने जय प्रकाश नारायण को मोहरा बनाया और एक प्रतिष्ठित राजनेता होने के बावजूद भी वह उस चक्रव्यूह में फंस गए। जब जनता पार्टी सरकार बनी जय प्रकाश नारायण को उन्होंने भुला दिया और उनका पूरा वचर्स्व समाप्त हो गया। मृत्यु होने पर जय प्रकाश नारायण को कोई उस तरह का सामान नहीं मिला जिसके वह हकदार थे जबकि उन्होंने उस आंदोलन का सूत्रपात किया था जिसने श्रीमती इंदिरा गाँधी को सत्ता से हटाया था।

अन्त में हम कह सकते है कि आपातकाल खास तरह की परिस्थितियों में हुआ जिनकी पृष्ठभूमि में इंदिरा गाँधी के विरुद्ध एक सोचे समझे षड्यंत्र की रूपरेखा बनी थी। लेकिन जो भी हो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि यह श्रीमती गाँधी की एक बहुत बड़ी भूल थी जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा और देश की जनतांत्रिक छवि पर एक धब्बा लगा। इंदिरा गाँधी की जयंती के अवसर पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बड़े नेता को ना सिर्फ अच्छा जन प्रतिनिधि, कुशल प्रशासक और लोकप्रियव्यक्त होना चाहिए, उसको उन सब राजनीतिक षडयंत्रों के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए जो निहित स्वार्थ रखनेवाले विरोधी चुपचाप उसके खिलाफ़ करते हैं।

****

लेखक : वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया गुरु एवं मीडिया मैप के संपादक है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सौ वर्ष: एक आलोचनात्मक मूल्यांकन

डॉ. सतीश मिश्रा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने इस वर्ष 11 अक्टूबर को अपने वार्षिक विजयादशमी संबोधन में अपने अनुयायियों से दलितों तक पहुंचने तथा 'डीप स्टेट' और 'वोकिज्म' के खतरों की ओर इशारा करने का आह्वान किया था, जिसे गंभीरता से लेने की जरूरत है।

इस साल भागवत का संबोधन खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने यह उस समय दिया जब आरएसएस अपनी स्थापना की शताब्दी मना रहा है। 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन नागपुर में स्वयंसेवकों के एक समर्पित समूह द्वारा आरएसएस की स्थापना की गई थी। स्थापना बैठक में पांच लोगों ने भाग लिया था जिनमें केशव बलिराम हेडगेवार, बीएस मोनजे, वीडी सावरकर के भाई गणेश दामोदर सावरकर, एलवी परांजपे और बीबी ठोलकर शामिल थे।

सभी संस्थापक सदस्यों में एक बात समान थी कि इस्लाम और मुसलमानों के प्रति गहरा अविश्वास और घृणा थी। हेडगेवार मुसलमानों को "यवन सांप" कहते थे - हिंदी में यूनानियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यह शब्द अक्सर विदेशियों के लिए इस्तेमाल होता है। आरएसएस के संस्थापक प्रमुख का मानना था कि सभी मुसलमान 'राष्ट्र-विरोधी' हैं।

1923 में नागपुर में हुए हिंदू-मुस्लिम दंगे आरएसएस की स्थापना का तात्कालिक कारण थे, क्योंकि हेडगेवार सावरकर की पुस्तक 'हिंदुत्व: हिंदू कौन है?' से प्रभावित थे, जिसमें लेखक ने विस्तार से बताया था कि हिंदुओं की मुख्य कमजोरी यह थी कि हिंदू समाज संगठित नहीं था और यही कारण है कि इसे पहले मुसलमानों और फिर अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। हिंदू समाज में अनुशासन की कमी हिंदुओं की दुखद दुर्दशा के लिए सबसे मजबूत कारकों में से एक थी, जो उपमहाद्वीप के मूल निवासी थे।

वास्तव में सावरकर की पुस्तक आरएसएस सहित हिंदू एकीकरण के सभी प्रयासों के लिए मार्गदर्शक बन गई।

इस पृष्ठभूमि में, भागवत के इस साल के वार्षिक संबोधन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है ताकि पंक्तियों के बीच उनके शब्दों के वास्तविक अर्थ को समझा जा सके। आरएसएस प्रमुख ने दावा किया कि जाति और सांप्रदायिक आधार पर देश को विभाजित करने के लिए एक 'डीप स्टेट' काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि 'डीप स्टेट' क्या होता है और इसके सदस्य कौन हैं।

आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अपने वार्षिक विजयादशमी संबोधन में दलितों से संबंध मजबूत करने और 'डीप स्टेट' और 'वोकिज्म' के खतरों पर जोर दिया। आरएसएस की स्थापना के शताब्दी वर्ष में दिए गए इस भाषण में भागवत ने समाज पर 'वोकिज्म' के प्रभाव और कथित छिपी शक्तियों के खिलाफ चेतावनी दी, जो आरएसएस के पारंपरिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। भाषण में खासतौर से प्रगतिशील विचारधाराओं और दलित-समाज के मुद्दों के प्रति उनकी धारणा सामने आई, जो राजनीतिक समीकरणों के मद्देनजर महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

कैम्ब्रिज डिक्शनरी कहती है कि 'डीप स्टेट' में "सैन्य, पुलिस या राजनीतिक समूह जैसे संगठन शामिल होते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे विशेष हितों की रक्षा के लिए गुप्त रूप से काम करते हैं और बिना निर्वाचित हुए या दूसरे शब्दों में बिना लोकप्रिय जनादेश के देश पर शासन करते हैं।"

अन्य लोग इसका सारांश देते हैं कि यह लोगों का एक समूह है, आम तौर पर सरकारी एजेंसियों या सेना के सदस्य, जिनके बारे में माना जाता है कि वे नीति के गुप्त हेरफेर या नियंत्रण में शामिल हैं। 'डीप स्टेट' का अर्थ एक समानांतर सरकार भी है जो राज्य की राजनीतिक संरचनाओं से स्वतंत्र रूप से संचालित होने वाली शक्ति के "संभावित रूप से गुप्त" और "अनधिकृत" नेटवर्क से बनी है।

अब एक सवाल अपने आप उठता है जिसे भागवत से पूछा जाना चाहिए और यह उनकी नैतिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि वे इस बारे में विस्तृत जानकारी दें और आम नागरिकों के साथ जानकारी साझा करें। जिस "डीप स्टेट" के बारे में वे चेतावनी दे रहे हैं, उसके बारे में तथ्य देकर वे अंधेरे में तीर नहीं चला सकते।

अन्यथा, आरएसएस में 'डीप स्टेट' के सभी गुण मौजूद हैं क्योंकि यह 1947 से ही एक ऐसे 'राज्य' की स्थापना के लिए काम कर रहा है जो कई मायनों में देश के संविधान को कमजोर करता है। हाल ही तक, आरएसएस के वित्त का ऑडिट नहीं किया जाता था और इसके खातों को कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता था। आरएसएस सरसंघचालक या उसके प्रमुख का चयन नब्बे के दशक तक गुप्त रहता था क्योंकि

वर्तमान प्रमुख अपने उत्तराधिकारी का नाम एक सीलबंद लिफाफे में छोड़ जाते थे जिसे उनकी मृत्यु के बाद खोला जाता था। राष्ट्रीय तिरंगा न तो आरएसएस के कार्यालयों पर फहराया जाता था और न ही नागपुर में इसके मुख्य मुख्यालय पर।

कई महत्वपूर्ण अधिकारी, न्यायाधीश, सशस्त्र बल के कर्मचारी आरएसएस के सदस्य थे, हालांकि उनकी सदस्यता कभी सत्यापित नहीं की जा सकी क्योंकि संगठन ने कभी अपने सदस्यों का रिकॉर्ड नहीं रखा। अपने सदस्यों के माध्यम से आरएसएस ने जानकारी एकत्र की और ऐसी नीतियों का मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीति तैयार की, जो संघ के आकलन में हिंदू विरोधी थीं, हालांकि इसकी आधिकारिक हिंदुत्व विचारधारा सनातन धर्म के सिद्धांतों और मार्गदर्शक दर्शन से काफी अलग थी, जिसने बड़े पैमाने पर हर विश्वास को पनपने दिया और अस्तित्व में रहने के लिए पर्याप्त जगह दी और इसे अपने में से एक बनाने के लिए आगे आया।

हालांकि आरएसएस 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या में सीधे तौर पर शामिल नहीं था, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार था क्योंकि इसने राष्ट्रपिता के प्रति नफरत पैदा करने के लिए अनुकूल माहौल बनाया था। आरएसएस हिंदू महासभा के साथ अपने करीबी संबंधों से इनकार नहीं कर सकता, जिसके सदस्य नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या की थी। आरएसएस ने कभी भी गोडसे के महिमामंडन को रोकने या उसके खिलाफ बोलने का गंभीर प्रयास नहीं किया, जिससे हिंसा के पंथ को बढ़ावा मिला।

भागवत ने कहा कि देश की एकता के लिए खतरा 'वोकिज्म' और 'सांस्कृतिक मार्क्सवाद' से है। आरएसएस प्रमुख ने तर्क दिया कि ये ताकतें पहले देश की संस्कृति पर हमला करती हैं और फिर उसके शिक्षण संस्थानों में घुसपैठ करती हैं, असंतोष को बढ़ावा देती हैं और लोगों को अपनी विरासत से घृणा करने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने कहा, "समाज में प्रत्यक्ष संघर्ष पैदा होते हैं और व्यवस्था, कानून और शासन के प्रति अविश्वास के माध्यम से अराजकता और भय का माहौल बढ़ता है, जिससे उनके लिए अपना वर्चस्व कायम करना आसान हो जाता है।"

भागवत के शब्दों को बेहतर ढंग से समझने के लिए बारीकी से विश्लेषण करने की जरूरत है और इसके लिए 'वोकिज्म' की परिभाषा पर गौर करना होगा। इसका शब्दकोशीय अर्थ है 'व्यवस्थागत अन्याय और पूर्वाग्रहों के प्रति संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति के रूप में उदार प्रगतिशील विचारधारा और नीति को बढ़ावा देना'।

शब्द की उपरोक्त परिभाषा में भागवत कुछ भी नया नहीं कह रहे थे, बल्कि वे

आरएसएस के शताब्दी वर्ष में मोहन भागवत के विजयादशमी भाषण ने संगठन के मूल सिद्धांतों और विचारधाराओं पर प्रकाश डाला, जिसमें दलित समुदाय तक पहुंचने और वोकिज्म तथा डीप स्टेट से जुड़े खतरों का उल्लेख किया गया। भागवत के विचारों में प्रगतिशील विचारधाराओं के प्रति संघ का पारंपरिक दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ, वहीं राजनीतिक परिदृश्य में आरएसएस और भाजपा के लिए दलितों की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया। उनके शब्दों को व्यापक रूप से राजनीतिक समीकरणों और संघ की दशकों पुरानी नीतियों से जोड़कर देखा जा रहा है।

केवल समाजवाद और साम्यवाद जैसी प्रगतिशील विचारधाराओं के बारे में आरएसएस के पुराने दृष्टिकोण को दोहरा रहे थे, जिसका उद्देश्य समाज के दबे-कुचले और वंचित वर्गों के साथ-साथ महिलाओं की मुक्ति और उन्हें सामाजिक-राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में समान भागीदार बनाना था। साम्यवाद जैसी वामपंथी विचारधाराओं को आरएसएस और सावरकर के इस्लाम और मुसलमानों की तरह दुश्मन घोषित किया गया।

भागवत द्वारा आरएसएस कार्यकर्ताओं को दलितों के साथ संबंध मजबूत करने का आह्वान मूल रूप से भाजपा की मदद करने के उद्देश्य से किया गया था, जिसे 2024 के लोकसभा चुनावों में चुनावी नुकसान उठाना पड़ा था। दलितों और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति आरएसएस की गहरी नफरत जगजाहिर है और यह कोई रहस्य नहीं है कि संघ ने कभी भी खुद को भीतर से सुधारने की कोशिश नहीं की।

सौ साल बाद भी वामपंथी विचारधाराओं और मुसलमानों के प्रति आरएसएस की अंतर्निहित और अंतर्निहित नफरत उसके अनुयायियों के लिए एक मजबूत बंधन और प्रेरणा शक्ति बनी हुई है। यह अपने मूल मूल्यों पर अडिग है और बदलते समय और स्थान में इसमें जरा भी बदलाव नहीं आया है।

यह राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने में सफल रहा है और अपने हिंदुत्व एजेंडे को लागू करने में भी सफल रहा है, लेकिन क्या आरएसएस की लोकप्रियता या इसकी सार्वभौमिक अपील पिछले दस दशकों में बढ़ी है?

यद्यपि 90 के दशक में केन्द्र में तथा उसके बाद 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा के सत्ता में आने से आरएसएस और भाजपा को संख्यात्मक रूप से बढ़ने में मदद मिली है, क्योंकि अवसरवादी और पद चाहने वाले लोग कभी भी सत्तारूढ़ दल में शामिल होने में नहीं हिचकिचाए हैं, जो उन्हें बढ़ावा दे सकता है, लेकिन लोकप्रिय धारणा में यह एक और ठग-सट्टेबाज संगठन बन गया है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी सार्वभौमिक अपील पांच महाद्वीपों में फैली हुई है, के विपरीत, आरएसएस को व्यापक रूप से एक ऐसे संगठन के रूप में माना जाता है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिथक, आधे झूठ और फर्जी आख्यानों का उपयोग करने से नहीं हिचकिचाता।

****

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

महिलाओं पर हिंसा : सुरक्षा और सम्मान की आवश्यकता

इंदु रानी सिंह

भारत के लोगों को महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने में काफी समय लगा है, हालांकि हमारे यहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिष्ठित महिलाएं रही हैं।

यद्यपि स्वर्गीय इंदिरा गांधी का कार्यकाल भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कार्यकालों में से एक था, विशेष रूप से 1971 के कार्यकाल और 1969 के विभाजन के दौरान, जिसमें बैंकों को पशुकरण और प्रिवीपर्स वापस लेने जैसे क्रांतिकारी कदम उठाए गए थे, पुरुषों ने कभी भी एक

फिल्म "सफ़ेद" और सुष्मिता सेन की "ताली" जैसी बॉलीवुड फिल्मों ने ट्रांसजेंडर समुदाय के संघर्षों को समाज के सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बरखा बिष्ट द्वारा अभिनीत "सफेद" एक ट्रांस व्यक्ति और विधवा की कहानी को दर्शाती है, जो समाज के कठोर रवैये के बीच एक-दूसरे में सांत्वना पाते हैं। इस तरह की फिल्में समाज की गहरी समस्याओं को उजागर करती हैं, जिससे परिवर्तन की उम्मीद जागती है।

महिला द्वारा उन्हें यह बताने को पसंद नहीं किया कि उन्हें क्या करना है।

यहां तक कि शंकर जैसे उदार कार्टूनिस्ट ने भी कई व्यंग्यात्मक कार्टून बनाए, जिनमें सबसे तीखा कार्टून इंदिरा गांधी को 'महिलाओं के मंत्रिमंडल में एकमात्र पुरुष' के रूप में दिखाया गया था।

लेकिन मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि दुनिया भर में फैली इन पारंपरिक रूढ़ियों से ध्यान हटाकर उस ओर ध्यान दिया जाए जिस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है तीसरा लिंग या जिसे हम ट्रांसजेंडर कहते हैं।

मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि यह वास्तविकता मुझे हाल ही में आई फिल्म "सफ़ेद" देखने के बाद समझ में आई - जिसने भारत और दुनिया भर में चर्चा बटोरी है। फिल्म की कहानी एक अकेले, परित्यक्त ट्रांस व्यक्ति और एक विधवा को दर्शाती है जो एक दूसरे में सांत्वना पाते हैं। भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्रियों मीरा चोपड़ा और अभय वर्मा ने फिल्म में अभिनय किया और समाज में ट्रांस लोगों और विधवाओं के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार को सफलतापूर्वक दर्शाया।

"हर कोई ऐसी फिल्म बनाना चाहता है जो लोगों को खुश करे, सब कुछ सकारात्मक तरीके से दिखाए और अंत सुखद हो, लेकिन 'सफेद' जैसी फिल्में बनाना, जो समाज के अंधेरे पक्ष को दर्शाती हैं, साहस का काम है," फिल्म में ट्रांस व्यक्ति राधा की भूमिका निभाने वाली भारतीय अभिनेत्री बरखा बिष्ट ने कहा। "लोग कह रहे हैं कि हमने यह फिल्म लोगों के प्यार के लिए बनाई है, लेकिन मैं

भारत में लैंगिक समानता की दिशा में एक लंबी यात्रा रही है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी प्रभावशाली भूमिका निभाई, लेकिन उन्हें भी समाज में गहरे रूढ़िवादी दृष्टिकोण का सामना करना पड़ा। हालाँकि, वर्तमान में अधिक ध्यान ट्रांसजेंडर समुदाय की ओर मोड़ने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जो अभी भी सामाजिक भेदभाव और पूर्वाग्रहों का सामना कर रहे हैं।

इससे सहमत नहीं हूं, हमने लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए ऐसा किया है। हमारे समाज में, हमारे पास ऐसे लोगों का एक वर्ग है, जिन्हें अक्सर बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। लोग उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। प्यार से ज़्यादा, हमें लोगों से सहानुभूति की ज़रूरत है।"

सुष्मिता सेन अभिनीत 'ताली' फिल्म भी थी, जिसका समापन 2014 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ होता है, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा।

हालाँकि, कुल मिलाकर बॉलीवुड उनके प्रति बहुत निर्दयी रहा है और उन्हें अपराधी और जबरन वसूली करने वाले के रूप में चित्रित करता रहा है।

इससे मेरे मन में यह विचार आया कि हमारे मानस में यह भेदभाव क्यों विद्यमान है, जबकि महाभारत में शिखंडी के रूप में इस समुदाय का बहुत प्रशंसनीय उल्लेख किया गया है।

हम साहित्य से यह भी जानते हैं कि ट्रांसजेंडर शाही घरानों में सबसे विशेषाधिकार प्राप्त समुदाय थे, क्योंकि उन्हें राजा और रानी या 'हरम' दोनों में मुफ्त पहुंच प्राप्त थी।

लेकिन बचपन से ही मैं इन ट्रांसजेंडरों के बारे में कहानियां सुनता आ रहा हूं कि वे ऐसे घरों में जाते हैं जहां कोई अप्राकृतिक प्राणी पैदा होता है और माता-पिता तथा रिश्तेदारों की ओर से ज्यादा प्रतिरोध के बिना ही उसे अपने साथ ले जाते हैं।

वास्तव में, उन्हें लगा कि यह 'अच्छा छुटकारा' है क्योंकि समाज उन्हें और उनके बच्चे को जीवन भर मज़ाक में उड़ाता रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वे खुद ट्रांसजेंडरों को गुंडों और जबरन वसूली करने वालों का गिरोह समझते थे जो पैसे ऐंठने के लिए विवाह और बच्चे के जन्म के समय आते थे।

महाभारत में शिखंडी और ऐतिहासिक शाही दरबारों में ट्रांसजेंडर समुदाय की भूमिका को देखते हुए आश्चर्य होता है कि आधुनिक भारत में इनका आज भी सम्मानजनक स्थान क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 2014 का ऐतिहासिक फैसला, जिसने ट्रांसजेंडरों के मौलिक अधिकारों को मान्यता दी, एक बड़ा कदम है, लेकिन इसे जमीन पर लागू करना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है।

लेकिन इस बात पर विचार करें कि क्या उनके पास जीवित रहने का सम्मानजनक विकल्प है, भारतीय संविधान के तहत गारंटीकृत 'सम्मानपूर्ण जीवन' की तो बात ही छोड़िए।

भारत इन ट्रांसजेंडरों के लिए एक काला धब्बा बना हुआ है क्योंकि कई देशों में वे चुनाव लड़ चुके हैं और संसद या कांग्रेस में सीटें जीत चुके हैं। उनमें से कुछ भारत में भी चुने गए हैं, लेकिन उनके कार्यकाल को कभी समाज और पूरी तरह से एकतरफा मीडिया रिपोर्टिंग द्वारा उजागर नहीं किया गया।

मैं लंबे समय से एक समुदाय के खिलाफ इस जन्मजात पूर्वाग्रह के बारे में सोच रहा हूं, जो किसी गलती (यदि वह गलती है) के लिए जिम्मेदार नहीं है।

बहुत बाद में मनुष्य ने, हाँ, वे मनुष्य ही हैं, अपने शरीर में रहने के अधिकार का प्रयोग करना शुरू किया, जिससे वे सहज हैं और अपने लिंग को बदलने के लिए ऑपरेशन करवाए। लेकिन यह भी बहुत दुर्लभ है।

2014 में (भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने के 64 वर्ष बाद) सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय (भारतीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा बनाम सर्वोच्च न्यायालय) में उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया।

देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया कि क्या गैर-द्विआधारी लिंग पहचान की अवहेलना करना भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

अदालत ने मामले को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत गठित एक 'विशेषज्ञ समिति' को भेज दिया।

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय अब भी सामाजिक बहिष्कार और नकारात्मकता का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिंग पहचान के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करना एक ऐतिहासिक निर्णय है, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव तभी होगा जब जागरूकता और स्वीकृति का माहौल बनेगा। यह समय है कि लेखकों, फिल्म निर्माताओं और सरकारों का समर्थन इस समुदाय के प्रति सकारात्मक बदलाव लाए।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अन्य बातों के अलावा यह माना कि लिंग पहचान का तात्पर्य जैविक विशेषताओं से नहीं है, बल्कि यह किसी के लिंग के बारे में जन्मजात धारणा से है।"

इसलिए अदालत ने फैसला दिया कि ट्रांसजेंडर संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19(1) और 21 के तहत मौलिक अधिकारों के हकदार हैं, जिन्हें मूल अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के अंतर्गत भी संदर्भित किया गया है।

इससे किसी भी चिकित्सा परीक्षण या जैविक परीक्षण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जो उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन करता हो।

मैं उम्मीद करता हूं कि लेखक, फिल्म निर्माता तथा केंद्र और राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरी तरह से पालन करेंगी और जागरूकता फैलाएंगी, ताकि ट्रांसजेंडर होने का कलंक फैसले को नकार न दे और उन्हें अपराध और नकारात्मकता के भंवर में न धकेल दे।

****

लेखिका एक गैर सरकारी संगठन प्रयास के कार्यकारी निदेशक है।

कड़वी-मीठी गोली

लेखक दिनेश वर्मा के बारे में

लेखक, दिनेश नारायण वर्मा, भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी हैं, अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपना दिल और आत्मा लेखन में लगा दी और 2016 में पीपुल्स सिंडिकेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित अपनी पहली किताब 'माई टाइम्स माई टेल्स' से इसकी शुरुआत की, जो बरेली, यूपी से दिल्ली के हलचल भरे महानगर तक की उनकी यात्रा के दौरान हुई घटनाओं और प्रकरणों पर आधारित सत्ताईस कहानियों का संग्रह है।

श्री वर्मा ने 'ए फैसिनेटिंग ट्रिप टू ह्यूमन्स मैन्युफैक्चरिंग साइट' लिखने में दूसरा प्रयास किया, जो स्पष्ट रूप से एक अवधारणा पुस्तक थी जो मनोरंजक तरीके से मानवीय स्थिति पर एक अभिनव नज़र डालती है।

लघु कथाओं और लेखों 'मेरे समय की मेरी कहानियां' के हिंदी संस्करण के प्रकाशन के बाद, हाल ही में प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तक 'द ब्लेस्ड कर्स' पाठकों, विशेषकर युवाओं को स्वतंत्रता के आसपास के वर्षों में ले जाने की उनकी दीर्घकालिक इच्छा का परिणाम है, ताकि वे अपने पूर्वजों के दैनिक जीवन की कठोर वास्तविकताओं से परिचित हो सकें।

संलग्न कथा उनकी पुस्तक मेरे समय की मेरी कहानियाँ से ली गयी

*- **संपादक***

मध्यान्तर की घंटी जैसे ही बजी हम सब अपनी अपनी कक्षाओं से निकलकर उस बड़े चबूतरे के पास कतारों में इकट्ठे हो गए जहाँ स्कूल की सारी गतिविधियाँ एवं सांस्कृ तिक कार्यक्रम आयोजित होते थे। लेकिन उस दिन जो होने वाला था वह बड़ा ही अनोखा था। प्रशासन के आदेश अनुसार हमें वहाँ उपस्थित रह कर एक ऐसे विद्यार्थी को सज़ा प्राप्त करते हुए देखना था जिसने अपनी शैतानी की हर हद पार कर दी थी। हम अपने स्थान पर खामोश सर झुकाए खड़े थे और बड़ी बेचैनी से उस विद्यार्थी के आने का इन्तज़ार कर रहे थे जिस को सजा मिलनी थी। थोड़े इन्तज़ार के बाद वह आठवी कक्षा का विद्यार्थी एक अध्यापक के साथ अपना सर झुकाए सीढ़ियों पर चढ़कर आँखे ज़मीन पर गाड़े चबूतरे पर ऐसे जाके खड़ा हुआ जैसे भेड़ कसाई की छुरी चलने से पहले सहमी खड़ी होती है।

और फिर आए प्रधानाचार्य साहब जो एक हाथ से अपनी दाढ़ी सहला रहे थे और दूसरे हाथ से अपना बेंत अपने ही अन्दाज़ में घुमा रहे थे। जब कभी भी हमारे हेडमास्टर साहब सामने होते तो हम सब दहशत के मारे कांपते हुए इधर-उधर छिपने की कोशिश करते थे। उनके पदचापो की आवाज़ कानों में पड़ते ही हम मुँह छिपाते फिरते थे। जहाँ वह अपनी प्रशासनिक क्षमताओं के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे वहीं सम्बन्धित विषयों के ज्ञान के लिए भी बहुत आदर से देखे जाते थे। उनका डर हर विद्यार्थी के मन में समाया हुआ था। वह म्युनिसिपल बोर्ड का बारहवीं कक्षा तक का स्कूल था जहाँ हर सामाजिक स्तर के लोगों के बच्चें पढ़ा करते थे। वहाँ एक ओर नवाबों, ज़मीदारों के बच्चें पढ़ते थे तो दूसरी ओर छोटे दुकानदार, बढई, कारीगरों के बच्चें भी पढ़ते थे। एक अजीब सा मिश्रण था विद्यार्थियों का उस स्कूल में। कुछ विद्यार्थी डरे और सहमे रहते थे और कुछ हर समय लड़ने को तैयार जो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते थे। विद्यार्थियों के ऐसे समूह को काबू में रखने के लिए एक सख्त अनुशासनिक प्रधानाचार्य की ही आवश्यकता थी जो अपने निष्पक्ष व्यवहार और अनुकर्णीय व्यक्तित्व द्वारा ही अनुशासन का स्वस्थ वातावरण पैदा कर सकते थे।

प्रधानाचार्य अपनी काली शेरवानी पहने हुए और हाथ में एक लम्बा बेंत लेकर उस विद्यार्थी के सम्मुख कुछ देर खड़े रहे और फिर, बिना किसी भूमिका के, उस विद्यार्थी पर बेंतो की बौछार कर डाली। विद्यार्थी पर बेंत पड़ते जाते थे और वह भयानक हमले से बचने के लिए, अपने शरीर को सिकोड़ कर, पीछे हटता जा रहा था। प्रधानाचार्य के बहादुर से बहादुर चाटूकारों में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे बढ़कर उन्हें रोक सकें। हालाँकि उनमें से कुछ को अवश्य यह दिखाने कि लालसा रही होगी कि वे उनके कितने वफादार थे। वह विद्यार्थी कोई और नहीं था बल्कि प्रधानाचार्य का स्वयं का पुत्र था जिसकी शैतानी हरकतों के बारे में सब ही जानते थे।

प्रधानाचार्य का अपने ही पुत्र पर स्कूल के समस्त विद्यार्थियों के सामने बेंत से

मारना उनकी निष्पक्षता का उदाहरण था खास तौर से उस स्कूल में जहाँ उच्च घरानों के बच्चों के माता पिता प्रधानाचार्य पर काफी दवाब डालते रहते थे और हर प्रकार का जोर डालकर उन से पक्षपातपूर्ण सुविधा प्राप्त कर पाने का प्रयत्न करते थे। लेकिन यह प्रधानाचार्य दूसरी ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने अपने सिद्धान्तों से समझौता करना सीखा ही नहीं था। वह किसी किस्म की अनुशासनहीनता और गैरजिम्मेदाराना व्यवहार बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे।

यह उस जमाने कि बात है जब बड़ी बड़ी कक्षा-कक्षाओं में एक बड़ा सा कपड़े का पंखा प्रयोग में लाया जाता था जिसे एक ओंघता हुआ चपरासी मशीनी अंदाज़ में दरवाजे पर बैठ कर खीचता रहता था। वह एक बड़ा रोमांचक दिन था जब उस कपड़े के पंखे को हटा कर बिजली के पंखे लगाए गए थे। यह वह जमाना था जब अध्यापकों की पहचान उनके बेंत के स्वरूप से की जाती थी। बेंत उनकी सत्ता एवं उनकी शक्ति का प्रतीक था जिसे विद्यार्थी तो क्या उनके माता-पिताओं में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे तोड़ पाते चाहे वह कितने की बड़े नवाब, उद्योगपति या ज़मीदार क्यों न हो।

मुझे याद है कि हमारे एक अध्यापक जिनके हाथ में चाबियों का गुच्छा रहा करता था किसी भी दिशा में फेंक के मारते थे, लेकिन मैंने कभी किसी विद्यार्थी के चोट लगते नहीं देखा। उनका उद्देश्य केवल विद्यार्थीयों में डर पैदा करना था। यह उनका डर ही था जिसके कारण हम लोग इतनी समझदारी से व्यवहार करने लगे थे कि कहीं धोखे से भी हमारे व्यवहार से किसी अध्यापक को शिकायत न हो जाए। वह हमारे घर के लिए दिया हुआ रहा हो या क्लास में दिया हुआ अभ्यास या फिर हमारी कोई शैतानी हरकत, डर हमारे चारों तरफ ऐसे मंडराता रहता था जैसे भूत-प्रेत की परछाई। इन सब बातों के बावजूद कभी न कभी ऐसा मौका अवश्य आ जाता था जब हमें अध्यापक के रोष का शिकार होना पड़ता था। यह होता ही था चाहे हम गलत हों या सही।

ऐसा ही एक मौका तब आया जब बिना मेरी किसी गलती के एक अध्यापक ने मुझे झापड़ मारा और जब मैंने उन से उसकी खिलाफत की, तो मुझे और ज़्यादा झापड़ खाने पड़े। मतलब यह कि गलती हो या न हो, अध्यापक को हम चुनौती किसी रूप में नहीं दे सकते थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब वह हाथ जिनसे मुझे यह आशा थी कि वह मेरे ज़ख़्म पर मलहम लगाएंगे उन्होंने मेरी एक न सुनी।

सिसकते रोते जब मैंने अपनी पिटाई की कहानी सुनाई तो मेरी माँ की भावनाओं को तो जरूर झटका लगा मगर मेरे पिता जी पर ज़रा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह अध्यापक के विरुद्ध कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे और बार बार एक ही बात कह रहे थे कि मैंने कोई न कोई हरकत जरूर की होगी। जितना मैं अपने अध्यापक के लिए बुरा भला कहता उतना ही मेरे पिता जी गुस्से में आ जाते और मुझे बस यही लगता था कि बस अब मैं और पिटा। और यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक मुझ में रोने की शक्ति समाप्त नहीं हो गई।

मेरे आंसू जो हमेशा मेरे माँ-बाप को पिघला दिया करते थे उस दिन उनके गुस्से को ठंडा करने में नाकाम रहे। इस हादसे की याद बहुत दिन तक मुझे कुरेदती रही। आखिर एक दिन उस कड़वाहट को याद करके अपनी माँ से अपने पिता के उस व्यवहार के बारे में सवाल कर डाला। मैंने माँ से पूछा कि क्या वह वाकई यह समझते थे कि मैंने कुछ गलत किया था। पिताजी के उस अत्याचारी व्यवहार का खुलासा उस दिन माँ ने कुछ इस प्रकार से किया।

"तुम्हारे पिता जी यह जानते थे कि तुम ने कुछ गलत नहीं किया था। वह यह भी जानते थे कि तुम्हारे अध्यापक को कोई न कोई गलतफहमी रही होगी। लेकिन वह अपने बच्चों के सामने इस बात को कभी स्वीकार नहीं करते। वह नहीं चाहते थे कि उनके बच्चें कभी भी अपने अध्यापकों के प्रति असम्मानपूर्ण या दुर्व्यवहार का रवैया अपना सकें।

उनकी नज़र में अध्यापकों का दर्जा माँ-बाप से भी बड़ा होता है। वह यह मानते हैं कि बच्चों को बनाने में अध्यापकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनका यह मानना था कि बच्चें बिना गुरु के कुछ भी नहीं कर सकते। उनका यह भी मानना था कि बच्चों के माता-पिताओं को अध्यापकों के साथ सहयोग करना चाहिए। उन्होंने यह कड़वी गोली तुम्हारे गले से इसलिए उतारी क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों में अनुशासनहीनता की कोई भी भावना पैदा हो। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि अध्यापक सही थे या गलत।"

और अब जब मैं बड़ा हो गया और खुद न सिर्फ एक पिता बना बल्कि दादा भी बन गया तब मैंने यह महसूस किया कि जो थप्पड़ पिता से उस वक़्त खाए थे उनका असली मूल्य क्या था।

****

गधा आदरणीय है क्योकि गधेपन की है भरमार

अनूप श्रीवास्तव

इस देश मे गधों की कमी नहीं है बल्कि गधों की भरमार है। इसी लिए गधापन सर्वव्यापी है। आप को कदम कदम पर गधापन मिलेगा। ऐसा गधापन की आप अपना गधापन भूल जाएंगे। जिधर भी जाएंगे गधापन नजर आएगा। हर क्षेत्र में गधेपन की लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है।

आपको पढ़ने और समझने की गलती न हो ,इसलिए प्रारम्भ में ही यह साफ कर देना चाहता हूँ कि मै किसी गधे को प्रणाम नही कर रहा हूँ। गधे को तो मैं पूज्य और आदरणीय प्राणी मानता हूँ लेकिन गधेपन के सख्त खिलाफ हूँ। इसके बावजूद मैं गधेपन को प्रणाम करना अपना कर्तव्य और दायित्व मानता हूँ। इसलिए नहीं कि इंसानों की दो टांगो की तुलना में उसकी चार टांगे हैं और वह इंसानों से श्रेष्ठ प्राणी है,बल्कि अपनी दो अतिरिक्त टांगों से इंसानों को टंगड़ी या दुलत्ती मार कर गिरा भी सकता है। ये दो टांगे उसे लोकतंत्र ने प्रदान की है।

चुनाव जीत कर जो भी जनप्रतिनिधि बनता है उसके अधिकार में दो अतिरिक्त (प्रशासनिक अधिकार वाली) टांगे जुड़ जाती हैं। ये टांगे सामान्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक टँगड़ी मारने वाली होती हैं। देश की पुलिस बल इन्ही टांगो के बल पर लतियाया जाता है। क्या मजाल खाकी कानून का कवच ओढ़ सके। इधर उसने कोशिश की कि उधर पड़ी दुलत्ती और वह ताकत रिरियाने पर मजबूर हो जाती है। यही खाकी पर खादी की विजय है।

अब सवाल यह उठता है कि कानून क्या है वह सविधान,जो मूल विधि है, का चाकर है। यानी वह संविधान के लाखों,करोड़ों प्राविधानों की रक्षा करता है।इसके बावजूद वह उन लोगों की भी रक्षा करने को विवश है जो गाहे बिगाहे कानून तोड़ने हैं,लेकिन निर्वाचित जनप्रतिनिधि है।ऐसे में वह किसकी रक्षा करे? संविधान की या निर्वाचित जन प्रतिनिधि की। यह बड़ा पेचीदा सवाल है। आज तक इस सवाल का कोई सटीक उत्तर न तो समाज दे पाया है ,नही सरकार और न सुप्रीम अदालत।इसी को कहते हैं , गधापन और मैं इसी गधापन को एक बार फिर प्रणाम करता हूँ।

> *इस व्यंग्यात्मक लेख में लेखक देश में सर्वव्यापी "गधेपन" पर कटाक्ष करता है, जिसे वह हर क्षेत्र में पाता है—राजनीति से लेकर फिल्म, साहित्य और कानून तक। लेखक गधों का आदर करते हुए, केवल "गधेपन" को प्रणाम करने का आग्रह करता है, जो लोकतंत्र में व्याप्त असंगतियों, अव्यवस्थाओं और ढोंग का प्रतीक है। लेखक गधेपन की लक्ष्मण रेखा को पार न करने और दूर से ही उसका आदर करने का सलाह देता है, ताकि उसके प्रभाव से बचा जा सके।*

मित्रो!मुझे माफ़ करना।न माफ करना तो गरियाना। लेकिन इस सवाल पर गौर जरूर करना कि गधेपन की इस देश मे इतनी मान्यता क्यों है।

गधापन सिर्फ राजनीति में ही नहीं है। हॉलीबुड, बॉलीबुड और साहित्य में भी है। ऐसा नही होता तो 'फ्रेम टु प्रेम' अंग्रेजी फ़िल्म की नकल बॉलीबुड में क्यों होती। चूंकि हो रही है इसलिए मैं गधों को नहीं उनके गधेपन को प्रणाम करता हूँ। आप सबसे भी यही निवेदन करता हूँ कि इसे प्रणाम करें क्योंकि इसी में हमारा और आपका भविष्य सुरक्षित है। हमारे लोकतंत्र का भविष्य भी इसी में सुरक्षित है क्योंकि हमारे संविधान का अधिकांश गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है।

दोस्तों !मै कोई राष्ट्रद्रोही या जिहादी नहीं हूँ।मैं भी मदन मोहन मॉलवीय और नेहरू जैसा देशभक्त हूँ।मगर यह देश मेरी समझ से बाहर होता जा रहा है। पश्चिम में देखता हूँ तो एक लहर है। दक्षिण में देखता हूँ तो दूसरी लहर है। उड़ीसा में देखता हूँ तो लहर नहीं तूफ़ान है। पूर्वोत्तर में देखता हूँ तो हर राज्य में राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा बने हुए हैं। यानी हर तरफ गधेपन की सीपों- सीपों सुनाई दे रही है। अगर कोई आपसे पूछे गर्दभ श्रीमान !अगर आप वाकई स्वतंत्र हो गए तो कहाँ कौन सा तीर मारोगे? सरकार में बैठे नौकरशाहों ने दुलत्ती लगा दी तो कहाँ जाकर गिरोगे?इन सवालों का जवाब गधेपन के अलावा और क्या होगा। इसलिए मैं पूर्वोत्तर गधेपन को भी प्रणाम करता हूँ ।

सबसे अधिक मैं साहित्यिक गधेपन का आभारी हूँ। कविता, कहानी। नाटक और आधुनिक उपन्यासों में जो कलात्मक गधापन दृष्टिगोचर होने लगा है,उसके प्रति मैं नतमस्तक हूँ। कहानी में कहानी कम है शिल्प उसके सीने पर सवार है। उपन्यास में न्यास कम विन्यास अधिक हैं। कविता में कविता से अधिक वक्तव्य है। कुछ कहूँ तो कवि जूता लेकर पिल पड़ेंगे। इसलिए चुप रहना बेहतर। गधेपन को दूर से साष्टांग प्रणाम करना बेहतर।

दुलत्तियों से बचने का एक मात्र उपाय यही है कि आप गधेपन को प्रणाम करते हुए,उससे दस फिट दूर रहकर चलें भले ही सड़क गड्ढा युक्त क्यों न हो । मगर विकास हो रहा है या कहीं अटका हुआ है इस बारे में मुंह न खोलें।कुछ न कहें। वरना उसकी दुलत्ती आप बर्दाश्त नही कर पाएंगे। गधे पन की भी लक्ष्मण रेखा होती है। इस सच को न भूलें। गधे को नही , सिर्फ गधेपन को प्रणाम करें।

****

मीडिया मैप वेबसाइट पर

Media Map HOME | TODAY'S EDITION | आज का संस्करण

1 Oct

US Fed Rate Cut No Big Deal For Indian Economy

Prof Shivaji Sarkar

New Delhi | Tuesday | 1 October 2024

The recent decision by the US Federal Reserve to cut interest rates by 50 basis points (0.5%) after a four-year hiatus has sparked a global conversation. However, for India, this move may not be as advantageous as some might hope. While the global markets react, India

Media Map HOME | TODAY'S EDITION | आज का संस्करण

22 Oct

गाय भाजपा राजनीति का एक भावनात्मक मुद्दा

प्रो राम पुनियानी

नई दिल्ली | मंगलवार | 22 अक्टूबर 2024

पिछले तीन दशकों से गाय भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भावनात्मक मुद्दा बन गई है। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और कई हिंदू इसे मां का दर्जा देते हैं। इसी धार्मिक आस्था का राजनीतिक उपयोग हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति ने किया है, जिससे समाज में ध्रुवीकरण हुआ है। आरएसएस और हिंदुत्ववादी विचारकों ने 'हिंदुत्व' को केवल एक धार्मिक अवधारणा

Media Map HOME | TODAY'S EDITION | आज का संस्करण | VIDE

24 Oct

बहराइच साम्प्रदायिक हिंसा

हिंदुत्व का शिकार बीजेपी विधायक और पुत्र

डॉ॰ सलीम ख़ान

नई दिल्ली | गुरुवार | 24 अक्टूबर 2024

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में साम्प्रदायिक हिंसा और राजनीतिक माहौल ने एक नया मोड़ लिया, जब बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के स्थानीय नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। यह मामला तब चर्चा में आया जब विधायक पर उनके ही पार्टी के सदस्यों द्वारा हमला किया गया, लेकिन इसके पीछे की कहानी कहीं अधिक गहरी और जटिल है।

Media Map HOME | TODAY'S EDITION | आज का संस्करण | VIDE

29 Oct

Hundred Years Of Rashtriya Swyamsevak Sangh: A Critical Appraisal

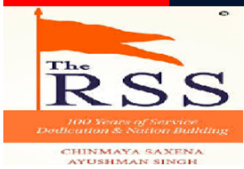

Dr Satish Misra

New Delhi | Tuesday | 29 October 2024

Rashtriya Swyamsevak Sangh Chief Mohan Bhagwat's exhortation to its followers in his annual Vijaydashmi address on October 11 this year asking them to reach out to Dalits pointing out to dangers from 'Deep State' and 'Wokeism' need to be taken seriously.

Bhagwat's address this year is particularly significant as he was at a time when the RSS is celebrating centenary of its existence. On 27 September 1925, the RSS was founded by a dedicated group of volunteers

Media Map HOME | TODAY'S EDITION | आज का संस्करण | VIDE

18 Oct

How British Left India A Pauper, Explain Nobel Laureates

Syed Khalique Ahmed

New Delhi | Friday | 18 October 2024

The 2024 Economics Nobel Prize winners – Daron Acemoglu, Simon Johnson, and James A. Robinson – all from the U.S.--have provided insights into why India, which was called a "golden bird" because of its wealth during the Mughal period from 1526 to 1761, turned into a pauper during the British Raj which replaced the Mughals as rulers.

Media Map HOME | TODAY'S EDITION | आज का संस्करण | VIDE

10 Oct

श्रद्धांजलि

रतन टाटा जो देश के विकास की प्रेरणा के अनवरत स्रोत थे

प्रशांत गौतम

नई दिल्ली | गुरुवार | 10 अक्टूबर 2024

भारत के महान उद्योगपति और प्रेरणास्रोत रतन नवल टाटा, जिन्होंने अपने लंबे कार्यकाल के दौरान टाटा समूह को एक वैश्विक शक्ति में परिवर्तित किया, का निधन बुधवार रात लगभग 11 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ। 86 वर्षीय टाटा जी को हाल ही में निर्जलीकरण की समस्या के कारण भर्ती कराया गया था। उनके निधन ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया है, और सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वाले भावुक संदेशों की बाढ़ आ रही है। उनका योगदान और उदारता हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।

Visit Our Bilingual Website: www.mediamap.co.in
Subscribe To Our YouTube Channel : Media Map News

SCHOLARS DESTINATION

RNI NO. : UPHIN/2016/68336

Please stay in Scholars destination and explore the beauty of surrounding areas .

PLEASE CONTACT

9045005700 | 9910322682 | www.sdmotel.com | info@sdmotel.com